ELITE IAS

समसामयिकी

जून–2019

8899999931/34

A-1 Chandra House, Top Floor, (Opp. ICICI Bank), Mukherjee Nagar, Delhi-09

ELITE IAS

Our Courses

For Civil Services Preparation

CLASSROOM PROGRAM

English / Hindi

Upgraded Foundation Course
General Studies

ONLINE COURSES

General Studies Video Classes
(Interactive)

ALL INDIA TEST SERIES

English / Hindi

General Studies
Prelims + Mains + Essay

CORRESPONDENCE COURSES

General Studies Pre. & Mains
(Interactive)

Index

आलेख

1.	अमेरिका इरान संबंध ईरान पर अमेरिका का मनोवैज्ञानिक हमला	1-2

कला, संस्कृति, समाज एवं सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

2.	नई शिक्षा नीति का मसौदा जारी	3-3
3.	दूरसंचार और सूचना समाज दिवस-2019	4-4
4.	मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ को एक्स-सर्विसमैन दर्जा देने हेतु मंजूरी	4-5
5.	केरल का प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव आरंभ	5-6
6.	उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने ओंगोल नस्ल की गाय को संरक्षित करने का आह्वान किया	6-7

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

7.	सरकार ने आठ कैबिनेट कमेटियों का गठन किया	8-9
8.	गृह मंत्रालय ने इंफोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द किया	9-10
9.	अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समिति को तीन महीने का समय दिया	10-11
10.	एनपीपी पूर्वोत्तर की पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी	11-12

अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

11.	बिश्केक में दूसरा शंघाई सहयोग संगठन मॉस मीडिया फोरम आयोजित	13-13
12.	अमेरिका ने ईरानी धातुओं पर प्रतिबंध लगाया	14-14
13.	समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश ताइवान बना	15-15
14.	सिंगापुर संसद ने फेक न्यूज विधेयक पारित किया	15-16
15.	भारत सरकार ने श्रीलंका के विद्रोही संगठन लिट्टे पर लगा प्रतिबंध बढ़ाया	16-17
16.	न्यूजीलैंड ने विश्व का पहला 'वेलबीइंग बजट' पेश किया	17-18
17.	डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की	18-19
18.	पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ समझौता राशि पर हस्ताक्षर किये	19-19

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

19.	एनएसएसओ एवं सीएसओ के विलय हेतु मंजूरी	20-20
20.	नाबार्ड ने ग्रामीण स्टार्टअप इकाईयों में 700 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की	21-21
21.	PM-KISAN योजना का विस्तार	21-22
22.	आरबीआई ने आरटीजीएस के जरिए लेनदेन की समय सीमा बढ़ाई	22-23
23.	डिजिटल भुगतान पर नंदन नीलेकणि पैनल ने आरबीआई को रिपोर्ट सौंपी	23-24
24.	3 से 7 जून तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जायेगा: आरबीआई	24-24
25.	आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से जुड़ेगा एमसीए 21 पोर्टल	24-25
26.	आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की	25-26

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं स्वास्थ्य

27.	अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण	27-27
28.	नासा ने आर्टेमिस-2024 मून मिशन के शेड्यूल की घोषणा की	27-28
29.	डीआरडीओ ने गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया	28-29
30.	सिम्बेक्स-2019 समुद्री युद्ध अभ्यास	29-30
31.	भारतीय नौसेना ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया	30-31
32.	भारतीय वायुसेना को मिला पहला अपाचे हेलीकॉप्टर	31-32
33.	केरल में खतरनाक निपाह वायरस की फिर पुष्टि	32-32
34.	एम्स में भारत का पहला मल्टी-स्क्लेरोसिस क्लिनिक खोला जायेगा	33-33
35.	भारतीय वायुसेना के एएन-32 विमान को जेट्रोफा बायो-फ्यूल उपयोग करने की मंजूरी दी गई	33-34
36.	RISAT-2B का सफल प्रक्षेपण	34-35
37.	अल्टिमा थुले पर मिले पानी की मौजूदगी के सबूत: नासा	35-36
38.	ब्रह्मोस मिसाइल के हवा से सतह पर मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण	36-36
39.	डिमेंशिया रोकथाम हेतु नये दिशा-निर्देश जारी	37-37
40.	नासा का पेलोड लेकर जाएगा चंद्रयान-2	38-38
41.	नासा अध्ययन:150 फुट सिकुड़ गया है चांद	38-39
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस:11 मई	39-40

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

43.	अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस:22 मई	41-41
44.	गंगा बेसिन क्षेत्र में रूद्राक्ष के वृक्ष लगाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	42-42
45.	एनजीटी ने 18 राज्यों से अपशिष्ट जल के इस्तेमाल पर कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया	43-43
46.	भारत में वायु प्रदूषण से हर साल 5 साल से कम उम्र के 1 लाख बच्चों की मौत: अध्ययन	44-44
47.	आयरलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की	44-45
48.	विश्व पर्यावरण दिवस: 05 जून	45-46
49.	शोधकर्ताओं द्वारा हिम युग के समयावधि का समुद्री जल खोजा गया	46-47

अन्य`बरें

50.	पाकिस्तान ने भारत में मोईन उल हक को अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया	48-48
51.	पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली	48-48
52.	देश की पहली महिला 'वित्तमंत्री' बनीं निर्मला सीतारमण	48-48
53.	अजीत डोभाल पुन: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त	48-48
54.	भारतीय लेखिका एनी जैदी को नाइन डॉट्स प्राइज 2019 का विजेता घोषित किया गया	48-49

55.	वाइस एडमिरल करमबीर सिंह ने नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला	49-49
56.	जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली	49-49
57.	नवीन पटनायक ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली	49-49
58.	ISSF वर्ल्ड कप: शूटर सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता	49-49
59.	ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने की इस्तीफे की घोषणा	50-50
60.	गोपाल श्रेष्ठ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एचआईवी संक्रमित पर्वतारोही बने	50-50
61.	ओमान की लेखिका जोखा अल्हार्थी को बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला	50-50
62.	World Cup 2019: अफगानिस्तान में पहली बार होगा वर्ल्ड कप का प्रसारण	50-50
63.	जोको विडोडो लगातार दूसरी बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने	51-51
64.	इरफान पठान सीपीएल खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय	51-51
65.	जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाले पहली महिला बनी	51-51
66.	IPL 2019 Final: मुंबई इंडियन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर चौथी बार खिताब जीता	51-52
67.	विश्व तंबाकू निषेध दिवस:31 मई	52-52
68.	लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के कमांडर नियुक्त	52-52
69.	प्रसिद्ध बिरहा गायक पद्मश्री हीरालाल यादव का निधन	52-52
70.	विश्व अस्थमा दिवस 07 मई को मनाया गया	52-52
71.	72वां कांस फिल्म महोत्सव, 2019	52-53

ELITE IAS

आलेख

अमेरिका - इरान संबंध

ईरान पर अमेरिका का मनोवैज्ञानिक हमला

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के डेढ़ साल रह गए हैं। क्या कुछ उसे ध्यान में रखकर ईरान से अदावत शुरू हुई है? दरअसल ट्रंप प्रशासन को ऐसा मुद्दा चाहिए, जिसकी गर्माहट लंबे समय तक बनी रहे। करीब 50 युद्धक विमानों और छह हजार फोर्स को लेकर चलने वाला अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन इस समय खाड़ी में है। कयास लगाया जा रहा है कि इसे ईरान से दो-दो हाथ करने के वास्ते तैयार किया गया है। उधर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड एयर फोर्स के प्रमुख आमीर हाजीजदेह को कह दिया गया है कि आप जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस बीच 13 मई 2019 को यूरोपीय संघ के मुख्यालय ब्रसेल्स में एक बैठक हुई। इस बैठक का तात्कालिक मकसद एक तरह से ईरान पर पश्चिमी दुनिया द्वारा मनोवैज्ञानिक दबाव पर पश्चिमी दुनिया द्वारा मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाना था। इसलिए इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो के संबोधान को खास तरीके से डिजाइन किया गया था। पोंपियो इस बैठक के बाद रूस रवाना हो गए। उनकी इस भागदौड़ को यह रूप दिया जा रहा है मानो जंग भागदौड़ को यह रूप दिया जा रहा है मानो जंग की आखिरी तैयारियों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा हो?

सवाल है क्या अमेरिका और ईरान सचमुच जंग के दरवाजे तक आ गए हैं? कुछ प्रेक्षक मान रहें है कि यह बहुत हद तक एक किस्म का मनोवैज्ञानिक युद्ध हे। शायद वास्तविक युद्ध न हो। लेकिन इस पूरी कवायद को इतना दबावपूर्ण तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि युद्ध से मिलने वाले फायदे बिना युद्ध के ही मिल जाएं। गौरतलब है कि कई वर्षों की बातचीत के बाद 2015 में संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थाई सदस्य देशों व जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत् ईरान में यूरोपीय कंपनियां तेल शोधन, मेडिसिन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश के लिए आगे बढ़ीं। कई हजार रोजगार के अवसर भी सृजित हुए। लेकिन यह खुशहाली चार दिन की चांदनी जैसी रही। ट्रंप ने मई 2018 से यह दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हम ईरान पर प्रतिबंध आयद कर रहें हैं, इसलिए शेष देश उससे रिश्ते न रखें।

पिछले साल अगस्त में अपने एक ट्वीट में ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर प्रतिबंध लगाने की आधिकारिक घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद कोहराम मचना स्वाभाविक था। दर्जनों यूरोपीय कंपनियां ईरान से अपना कारोबार समेट चुकी हैं, सैकड़ों रोजगार चले गए। अगस्त 2018 में ट्रंप ने यूरोपीय निवेशकों से कहा था कि आपके पास दो विकल्प हैं, या तो अमेरिका के वृहदाकार बाजार को चुन लीजिए या फिर ईरान के छोटे से मार्केट में कारोबार कीजिए। मतलब साफ था कि ईरान से धंधा करना है तो उन कंपनियों को अमेरिका में बैन किया जाएगा। इस धमकी पर निवेशकों का नुकसान होना ही था। यूरोप के जो छोटे कारोबारी ईरान में पैसे लगा चुके हैं, उनके बारे में मानकर चलिये कि वो लुट-पिट गए। अप्रैल 2018 से ट्रंप की वक्र दृष्टि ईरान पर पड़ी है। उसकी वजह सुनने पर लगता है कि कहीं न कहीं इजराइल के यहूदी लिंक ने आग में आहुति का काम तो नहीं किया है? ऐसा कायास इसलिए लगाया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि ट्रंप की मध्य-पूर्व नीति उनके यहूदी मूल के दामाद जरेद कुशनर के दम पर चल रही है।

वैसे एक बात यह भी है कि ईरान के मामले में ट्रांप ने जिस तरह की हठधर्मिता शुरू की है, उससे वह खुद कठधरे में खड़े हो सकते है। विएना स्थित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण (आइएई) ने माना है कि जनवरी 2016 से ईरान ने संधि की सभी शर्तों को माना है। साल 2015 के समझौते में ईरान ने अपने करीब नौ टन अल्प संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करके 300 किलोग्राम पर लाने की शर्त स्वीकार की थी और उस दिशा में आइएईए के मुताबिक उसने शर्त का उल्लंघन नहीं किया। मगर अब ट्रंप की एक तरफा कार्रवाई से त्रस्त ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी ने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों- रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के अतिरिक्त जर्मनी को जानकारी दी है कि हम संधि से आंशिक रूप से अलग हो रहे हैं। इस समय चुनाव में

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

व्यस्त भारत का कोई भी नेता ईरान को लेकर पैदा तेल संकट पर गंभीर नहीं है। चुनाव के किसी मंच पर इस विषय के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया। ट्रंप ने धमकाया है कि कोई भी देश ईरान से तेल खरीदता है तो उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को पता है कि चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है जो ईरान से सर्वाधिक कच्चा तेल आयात करता है और उसकी कीमत डॉलर में नहीं, बल्कि रुपये में चुकाता है। भारत हर दिन सवा चार लाख बैरल तेल ईरान से लेता है। अमेरिका यह नहीं बता रहा है कि इस बैन के बाद विकल्प क्या है? बस हमने प्रतिबंध लगा दिया तो ईरान से तेल नहीं लेना है। आप तेल आयात बढ़ाना चाहें तो सऊदी अरब से बात करें। भारत प्रतिदिन सऊदी अरब से आठ लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है। रियाद इस ईरान से हो रहे विवाद का व्यापारिक लाभ उठाने में लगा हुआ है, इस सच से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सऊदी अरब से भारत का 28 अरब डॉलर का कारोबार कुछ महीनों में छलांग लगा सकता है। उसे हर हाल में ईरान का मार्केट शेयर खाना है। रियाद स्थित कंपनी 'आर्मको' के तेल रणनीतिकार इस समय मुंबई में बैठे क्या कर रहे हैं? यह खोज का विषय नहीं है, ईरान से अमेरिकी अदावत का दूरगामी फायदा सऊदी कैसे उठाना चाहता है, बड़ी बेशर्मी से यह सब कुछ स्पष्ट है। इसका एक उदाहरण बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, जहां आर्मको 10 अरब डॉलर की लागत से विशाल रिफाइनरी स्थापित कर रहा है। तेल के वैश्विक कारोबार में जो छीछालेदर जारी है, वह केवल ट्रंप की जिद की वजह से है। ईरान से पहले एक और तेल निर्यातक देश बेनेजुएला पर किस तरह डोनाल्ड ट्रंप की वक्र दृष्टि पड़ी हुई है, इसे पूरी दुनिया ने मूक दर्शक की तरह देखा है। इस चौध राहट को कैसे रोका जाए, इस बारे में कोई संगठित प्रयास नहीं हो रहा है। भारत कह चुका है कि हम किसी देश के एक पक्षी प्रतिबंध को नहीं मानते। मगर क्या यह सिर्फ कह देने भर से हो जाएगा?

❑❑❑❑

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कला, संस्कृति, समाज, तथा सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

नई शिक्षा नीति का मसौदा जारी

चर्चा में क्यों?

☞ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूसरी बार सरकार बनाने के पहले दिन नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया गया है. नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी.

नई शिक्षा नीति का मसौदा: प्रमुख सिफारिशें

- इसके तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है, साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है.
- इस मसौदा नीति में लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन के चार वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने तथा कई कार्यक्रमों के हटाने के विकल्प के साथ-साथ एम. फिल. प्रोग्राम को रद्द करने का भी प्रस्ताव किया गया है.
- इस मसौदा नीति के अनुसार, पी.एच.डी. करने के लिये या तो मास्टर डिग्री या चार साल की स्नातक डिग्री को अनिवार्य किया गया है.
- नए पाठ्यक्रम में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिये 5+3+3+4 डिजाइन (आयु वर्ग 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष) तैयार किया गया है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्कूली पाठ्यक्रम तक शिक्षण शास्त्र के पुनर्गठन के भाग के रूप में समावेशन के लिये नीति तैयार की गई है.
- यह मसौदा नीति धारा 12 (1) (सी) (निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिये अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण का दुरुपयोग किया जाना) की भी समीक्षा करती है.

अन्य प्रमुख सिफारिशें

- स्कूली शिक्षा के लिये एक स्वतंत्र नियामक 'राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण' (SSRA) और उच्च शिक्षा के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा.
- निजी स्कूल अपनी फीस निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र हैं, लेकिन वे मनमाने तरीके से स्कूल की फीस में वृद्धि नहीं करेंगे. 'राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण' द्वारा प्रत्येक तीन साल की अवधि के लिये इसका निधारण किया जाएगा.
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए शीर्ष निकाय 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' की स्थापना की जाएगी जो सतत् आधार पर शिक्षा के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और शिक्षा के उपयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिये उत्तरदायी होगा.
- स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिये गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा के लिये प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों के योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा.
- विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी.

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

दूरसंचार और सूचना समाज दिवस-2019

चर्चा में क्यों?

- विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस अर्थात वर्ल्ड टेलीकम्युनिशेन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा समाज में आये सामाजिक परिवर्तनों से लोगों को परिचित कराना है.
- वर्ष 2019 का विषय है - मानकीकरण की खाई को पाटना (Bridging the standardization gap)
- इस दिन लोगों के मूलभूत मानव अधिकारों के प्रति लोगों का ध्यान केन्द्रित करना तथा समाज के बेहतर विकास के लिए प्रस्तुत की गई सूचना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है. इसी के चलते वर्ष 1973 में मैलेगा-टोर्रीमोलिनोन्स में एक सम्मेलन में 17 मई को यह दिवस मनाये जाने की घोषणा की गई थी.

मानकीकरण की खाई को पाटना (Bridging the standardization gap)

- मानक स्थापित करना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (आईटीयू) के मिशन का एक बुनियादी स्तंभ है.
- आईटीयू मानक सभी सतत विकास लक्ष्यों के लिए आईसीटी में तेजी लाने में मदद करते हैं.
- 2019 का विषय आईटीयू सदस्यों और अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए निम्न अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा:
  - ITU के मानक बनाने की प्रक्रिया में विकासशील देशों की भागीदारी,
  - राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण प्रक्रिया में स्थानीय विशेषज्ञों को सशक्त बनाना; तथा
  - विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना.

दूरसंचार क्या है?

- एक एक संचार प्रणाली होती है जिसे किसी केबल, टेलीग्राफ या प्रसारण माध्यम द्वारा दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क करने के लिए उपयोग किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, उत्पादन और निर्यात दोनों के संदर्भ में भारतीय उद्योग के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र हैं. मौजूदा समय में इन्टरनेट और मोबाइल दूरसंचार के सबसे प्रमुख उपकरण हैं.

स्रोत: द हिंदू

मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ को एक्स-सर्विसमैन दर्जा देने हेतु मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ (एमएनएस) को भी एक्स-सर्विसमैन का दर्जा दिए जाने को मंजूरी दी गई. रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इसमें तकनीकी तौर पर एमएनएस अधिकारी एक्स-सर्विसमैन की दी गई परिभाषा में नहीं आते हैं, इसलिए सरकारी दस्तावेजों में इस परिभाषा का संशोधन किया जायेगा.

लाभ

- एक्स-सर्विसमैन का दर्जा दिए जाने पर एमएनएस अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत दोबारा कहीं नौकरी हासिल करने में आसानी होगी.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इससे राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए मौजूद नौकरियां हासिल करने में इन अधिकारियों को सुविधा होगी.
- इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों के बच्चों को कॉलेज में दाखिले में भी सुविधा मिलेगी.
- गौरतलब है कि एमएनएस अधिकारी पहले से ही Ex- servicemen Contributory Health Scheme (ईसीएचएस) सुविधा का लाभ हासिल कर पा रहे हैं.

मुख्य तथ्य

- थल, जल और वायु सेना में अहम भूमिका निभाने वाली 'फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स' अर्थात मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) की महिला अधिकारियों को जल्द ही दूसरे फौजियों की तरह एक्स सर्विसमैन का दर्जा प्राप्त होगा.
- यह दर्जा प्राप्त होने पर यह महिला अधिकारी सर्विस के दौरान अपनी आधिकारिक गाड़ी में स्टार प्लेट लगा सकेंगी, जो उनके रैंक और स्टेटस को दर्शाता है.
- महिला ऑफिसर्स लंबे वक्त से अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है.

पृष्ठभूमि

- एमएनएस अधिकारियों को न तो एक्स सर्विस मैन का स्टीकर दिया जाता है और न ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ब्रिगेडियर और उससे ऊंचे रैंक के अधिकारियों की तरह आधिकारिक गाड़ी में स्टार प्लेट और फ्लैग लगाने की इजाजत है, जो उनके स्टेटस को दर्शाता है.
- लड़ाकू सेना की एकमात्र 'मिलिट्री नर्सिंग सर्विस', जिसमें सभी महिलायें शामिल हैं, लगभग 15 वर्षों से अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं.
- इन मामलों में लगभग 28 ऐसे मामले हैं जिन पर महिला ऑफिसर्स ने बराबरी के लिए आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल (एएफटी) में अपील की है.
- महिला अधिकारियों ने इसके लिए आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल (एएफटी) में अपील की और 2010 में एएफटी ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमिशंड ऑफिसर्स की तरह एमएनएस ऑफिसर्स को भी रैंक और इंटाइटलमेंट में बराबरी का हक मिलना चाहिए.

स्रोतः द हिंदू

केरल का प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव आरंभ

चर्चा में क्यों?

☞ केरल का प्रसिद्ध उत्सव त्रिशूर पूरम 13 मई 2019 को आरंभ हुआ. उत्सव का आरंभ 54 वर्षीय हाथी द्वारा किया गया. वडक्कुमनाथन मंदिर में तेचीकोत्तूकावु रामचंद्रन (Thechikottukavu Ramachandran) नामक इस गजराज ने प्रतीकात्मक रूप से मंदिर के दक्षिणी प्रवेश द्वार को धक्का देकर खोला, जो उत्सव के शुभारंभ का संकेत था. यह उत्सव लगातार 36 घंटे तक मनाया जाता है.

मुख्य तथ्य

- यह केरल का वार्षिक उत्सव है जो वल्लुनावाडु क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस उत्सव में रंग-बिरंगे परिधानों में सजे लोग तथा हाथियों की साज-सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं.
- त्रिशूर पूरम में रात भर जहां पटाखे चलाए जाते हैं, हाथियों की झांकियां निकाली जाती हैं तथा प्रसाद का वितरण किया जाता है.
- त्रिशूर पूरम दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे केरल में आयोजित किया जाता है.
- इस उत्सव में स्थानीय ही नहीं बल्कि सैंकड़ों पर्यटक भी शामिल होते हैं. इसकी शुरुआत शक्थान थम्पूरन द्वारा की गई थी, शक्थान कोच्ची का एक शासक था.
- उस समय से ही दस मंदिरों को शामिल करके इस उत्सव को मनाया जाता है जिसमें परमेक्कावु, थिरुवमबाड़ी कनिमंगलम, करमकु, लल्लूर, चूरकोट्टुकरा, पनामुक्कमपल्ली, अय्यनथोले, चेम्बुकावु और नेथिलाकवु मंदिर शामिल हैं.
- उत्सव में 30 हाथियों को पूरी साज-सज्जा के साथ शामिल किया जाता है.
- इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ इलान्जिथारा मेलम नामक लाइव परफॉरमेंस भी आयोजित की जाती हैं. इस दौरान लगभग 250 कलाकार भाग लेते हैं.

हाथियों की भूमिका

- त्रिशूर पूरम उत्सव के अंतिम दिन श्रद्धालु तीस हाथियों के साथ झांकियां निकालते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है.
- पहला दल थिरुवमबाड़ी मंदिर तक जाता है. दूसरा दल परमेक्कावु भागवती मंदिर की ओर जाता है. प्रत्येक दल के पास भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है.

स्रोतः द हिंदू

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने ओंगोल नस्ल की गाय को संरक्षित करने का आह्वान किया

चर्चा में क्यों?

☞ भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने हाल ही में ओंगोल नस्ल की गाय को रक्षा करने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि यह नस्ल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है और हमें इसे बचाने की जरूरत है.

उपराष्ट्रपति ने विजयवाड़ा स्थिति स्वर्ण भारत न्यास में आयोजित एक कार्यक्रम में ओंगोल नस्ल की गाय पर एक विवरणिका भी जारी की. यह विवरणिका 1200 पेजों की है. इसमें साल 1885 से साल 2016 तक पशु इतिहास दिया गया है. पुस्तक में ओंगोल गाय पर किये जाने वाले अनुसंधान को भी शामिल किया गया है.

ओंगोल नस्ल की गायः

- ओंगोल पशु आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर कृष्णा, गोदावरी और गुन्टूर जिलों में पाए जाते है. आंध्रप्रदेश के ओंगोल क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण इसे ओंगोल नाम दिया गया है. ओंगोले गाय उचित मात्रा में दूध देती हैं. ये गाये प्रतिदिन 3 लीटर से 8 लीटर तक दूध देती है. ओंगोले नस्ल के जानवरों को बड़े पैमाने पर अमेरिका और ब्राजील में निर्यात किया गया है.
- भारत में गायों की 37 नस्लें पायी जाती है, जिनमें साहीवाल, गिर, लाल सिंधी, थारपारकर और राठी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लें हैं.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत में पायी जाने वाली गायों की विभिन्न प्रजातियो की सूची इस प्रकार है

- गीर: यह प्रजाति भारत में पायी जाने वाली गाय की प्रजातियों में सबसे अच्छी कोटि की प्रजाति मानी जाती है. यह गुजरात राज्य के गिर वन क्षेत्र और महाराष्ट्र तथा राजस्थान के आसपास के जिलों में पायी जाती है. यह गाय अच्छी दुग्ध उत्पादताकता के लिए जानी जाती है. इस गाय के शरीर का रंग सफेद, गहरे लाल या चॉकलेट भूरे रंग के धब्बे के साथ या कभी कभी चमकदार लाल रंग में पाया जाता है.
- साहीवाल: इस गाय को शरेड गोल्डश भी कहा जाता है और इसकी पहचान मुख्य रूप से इसके लाल रंग से की जाती है. साहीवाल गाय का मूल स्थान पाकिस्तान में है.
- लाल सिंधी: लाल सिन्धी गाय भारत में पाए जाने वाली एक ऐसी नस्ल है जो बहुत अधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है. यह मूलत: लाल रंग की होती है और साहीवाल प्रजाति की गायो की तुलना में दूध उच्यतम कोटि की होती है. यह नस्ल मध्यम ऊंचाई की होती है.
- राठी: राठी गोवंश राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं. इस नस्ल की गाय अत्यधिक दूध देने के लिये प्रसिद्ध है. गुजरात राज्य में भी राठी गाय बहुत पाली जाती है. यह गाय आमतौर पर भूरे रंग की होती है और इनकी त्वचा पर काले या सर रंग के धब्बे होते हैं. ऐसा माना जाता है कि इसका विकास साहीवाल, लाल सिंधी, थारपारकर और धनी के मेल से हुआ है.

  थारपारकर: यह प्रजाति सफेद सिंधी", "ग्रे सिंधी" और "थीरी" के नाम से भी जानी जाती है. इस प्रजाति की गायों में गर्मी सहिष्णुता और रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत अधिक होती है. थारपारकर गाय राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है. गुजरात राज्य के कच्छ में भी इस गाय की बड़ी संख्या है.

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

सरकार ने आठ कैबिनेट कमेटियों का गठन किया

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्र सरकार ने आठ कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है. इसमें गृह मंत्री सभी आठ कैबिनेट समितियों में शामिल हैं. इनमें से छह कमेटियों में खुद प्रधानमंत्री शामिल होंगे.

☞ सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश और विकास पर और बेरोजगारी से निपटने के लिए रोजगार और कौशल विकास पर समिति गठित की है. सुरक्षा पर भी समिति का गठन किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिति के अध्यक्ष होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके सदस्य बनाए गए हैं.

आठ कैबिनेट समिति इस प्रकार है:-

- अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट: अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट का कंपोजीशन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास रहेगा.
- कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमडेशन: गृह मंत्री अमित शाह, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल के पास रहेगा. इसके अतिरिक्त इस कमेटी में विशेष तौर पर जितेंद्र सिंह और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी शामिल किया गया है.
- कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स: कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, डीवी सदानंद गौड़, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, रवि शंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, डॉ एस जयशंकर, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं.
- कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स: इस कमेटी में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर और प्रहलाद जोशी को शामिल किया गया है. कमेटी में विशेष तौर पर अर्जुन राम मेघवाल एवं वी मुरलीधरन को भी शामिल किया गया है.
- कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स: कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, डॉ हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, अरविंद सावंत और प्रहलाद जोशी को शामिल किया गया है.
- कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी: कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं.
- कैबिनेट कमेटी ऑन इनवेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ: कैबिनेट कमेटी ऑन इनवेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त जिन मंत्रियों को जगह दी गई है उनमें अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल शामिल हैं.
- कैबिने ट कमेटी ऑन इम्पलॉयमेंट एण्ड स्किल डेवलेपमेंट: इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान, महेंद्र नाथ पांडे, संतोष कुमार गंगवार और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं. इसमें खास तौर पर नितिन गडकरी, हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी और प्रहलाद सिंह पटेल को शामिल किया गया है.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

क्या होती है कैबिनेट समिति?

- कैबिनेट समिति का गठन या तो सीधे प्रधानमंत्री कर सकते हैं या कैबिनेट कर सकती है. पीएम अधिकांश समितियों के प्रमुख होते हैं.
- प्रधानमंत्री यह भी निर्णय ले सकते हैं कि जिन मामलों की चर्चा विशिष्ट कैबिनेट समिति में हुई है उसकी चर्चा मुख्य कैबिनेट में भी की जा सकती है.
- कैबिनेट समिति की मुख्य भूमिका सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करना और अंतिम रूप देना है. जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होते हैं.
- सामान्य हाउसकीपिंग मुद्दे से संबंधित समितियों का उद्देश्य नियुक्ति और आवास से संबंधित मामलों को निपटाना है.
- लेकिन स्थायी समितियों का टर्म गवर्नमेंट ट्रांसक्शन नियम 1961 में परिभाषित किया गया है. कैबिनेट समितियां अस्थायी हैं.
- मुख्य निर्णयों पर विचार-विमर्श करने के अलावा, ये समितियां सरकार को अपने नेताओं के साथ-साथ अपने सहयोगियों को भी अच्छी जिम्मेदारी देने में मदद करती हैं.
- यदि पीएम चाहते हैं, तो वे उन सांसदों को शामिल कर सकते हैं जो विशेष आमंत्रित सूची के तहत कैबिनेट में नहीं हैं.

क्या कैबिनेट समितियों के गठन की कोई सीमा है?

- नहीं, क्योंकि वे अस्थायी समितियां हैं, जिनमें कोई निश्चित सीमा नहीं होती है. सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री जरूरत के आधार पर जितनी चाहें उतनी समितियां स्थापित कर सकती हैं. इस तरह की समितियां मूल रूप से मुख्य कैबिनेट से भार उठाने के लिए बनाई जाती हैं. जो हर मंत्रालय से संबंधित नीति पर चर्चा करती है और निर्णय लेती है, और निर्णय लेने में तेजी लाती है.

स्रोतः पीआईबी , द हिंदू

गृह मंत्रालय ने इंफोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द किया

चर्चा में क्यों?

☞ गृह मंत्रालय ने हाल ही में गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इंफोसिस फांउडेशन का पंजीकरण रद्द करने की घोषणा की है. इंफोसिस के खिलाफ नियमों के खिलाफ जाकर विदेशी चंदा प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है. गृह मंत्रालय के अनुसार नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है.

मुख्य तथ्य

- गृह मंत्रालय द्वारा इंफोसिस फाउंडेशन को वर्ष 2018 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था. गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि संगठन ने विदेशी धन की प्राप्ति और व्यय का पिछले कुछ वर्षों से वार्षिक ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया था. बार-बार पत्र जारी किए जाने पर भी यह कदम उठाना पड़ा है.
- गृह मंत्रालय ने पिछले साल 1,755 गैर सरकारी संगठनों को नोटिस दिए थे, जिनमें कुछ कंपनियां भी शामिल हैं.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

इंफोसिस फाउंडेशन

- इंफोसिस फाउंडेशन भारत में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में इंफोसिस द्वारा समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए की गई थी.
- यह फाउंडेशन शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, कला और संस्कृति, तथा निराश्रितों की देखभाल के क्षेत्रों में कार्यक्रमों का समर्थन करता है.
- यह फाउंडेशन शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ग्रामीण भारत में स्कूलों के साथ फाउंडेशन पार्टनर्स, और कम उम्र के बच्चों के बीच प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देता है.
- फाउंडेशन सामुदायिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ काम करता है. यह स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सड़कों का निर्माण करते हैं, जल निकासी प्रणाली और बिजली प्रदान करती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावितों का पुनर्वास करती है.

स्रोतः द हिंदू

अयोध्या विवादः सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समिति को तीन महीने का समय दिया

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट में 10 मई 2019 को पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समिति को तीन महीने (15 अगस्त तक) का और समय दिया है.
- कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को कहा था कि मध्यस्थता प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू होगी और समिति चार सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. मध्यस्थता कमेटी को इससे पहले 8 हफ्ते का समय दिया गया था लेकिन 10 मई 2019 को सुनवाई के दौरान कमेटी ने अतीरिक्त समय की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट के 8 मार्च के आदेश के बाद शुक्रवार को पहली सुनवाई हुई.

मामला क्या है?

- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2010 में अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को तीन पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा एवं राम लल्ला (राम मंदिर) के बीच बराबर बांट दिया था.
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2010 के फैसले के विरुद्ध सुनवाई किया जा रहा है.
- कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या के विवादित स्थल को रामजन्मभूमि करार दिया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील दायर की गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता पैनल का गठनः

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई में मामले को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानते हुए एक मध्यस्थता पैनल का गठन किया गया था.
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्षकारों के बीच आम सहमति की कमी की कारण से तीन सदस्यीप पैनल का गठन किया था.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस पैनल का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफएम कलीफुल्ला को बनाया गया था.
- इस समिति के अन्य सदस्यों में आध्यत्मिक गुरू और आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू शामिल थे.
- वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू कानूनी हलकों में एक प्रसिद्ध मध्यस्थ हैं.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश:

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मध्यस्थता की कार्यवाही बहुत ही गोपनी तरीका के साथ होनी चाहिए जिससे उसकी सफलता सुनिश्चित हो सके. मध्यस्थों समेत किसी भी पक्ष द्वारा व्यक्त किये गए मत गोपनीय रखे जाने चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इनका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

एनपीपी पूर्वोत्तर की पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी

चर्चा में क्यों?

☞ मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) को चुनाव आयोग से राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है.

मुख्य तथ्य

- इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पूर्वोत्तर के किसी स्थानीय पार्टी को यह दर्जा मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है।
- मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा की अध्यक्षता वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी इसके लिए सभी जरूरी अहर्ताएं पूरी कर ली थी।
- एनपीपी केंद्र में सत्तारुढ़ एनडीए का सहयोगी दल है. यह पहले से ही अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के चलते एनपीपी ने राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए जरूरी शर्तों को पूरा किया था. विधानसभा चुनाव में एनपीपी ने अरुणाचल प्रदेश में पांच सीटें जीती थी. 60 सीटों में से 21 सीटों के साथ एनपीपी मेघालय की सबसे बड़ी पार्टी है.

चुनाव आयोग के नियम

- चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, अगर कोई पार्टी चार राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता रखता है तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता रखने के लिए सभी आवश्यक शर्तें भी पूरी करती है.
- राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद देश में किसी भी अन्य राजनीतिक दल या प्रत्याशी को एनपीपी का 'किताब' वाला चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जा सकेगा.
- वर्तमान में कुल सात राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था. यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस थे.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) का राष्ट्रीय चिन्ह किताब है. एनपीपी की स्थापना पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा ने साल 2013 में की थी. संगमा पूर्वोत्तर के सबसे बड़े और लोकप्रिय सांसद रहे हैं. उन्होंने साल 2012 में कांग्रेस से अलग होकर पार्टी की स्थापना की थी. राजस्थान के किरोड़मल मीणा भी संगमा के साथ एनपीपी के सहसंस्थापक हैं. राजस्थान के विधानसभा चुनाव में साल 2013 में एनपीपी ने चार सीटों पर जीत दर्ज की थी. मणिपुर विधानसभा चुनाव साल 2017 में एनपीपी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, भारत और विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

बिश्केक में दूसरा शंघाई सहयोग संगठन मॉस मीडिया फोरम आयोजित

चर्चा में क्यों?

☞ किर्गिजस्तान के बिश्केक में 23 मई से 26 मई 2019 तक दूसरा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) मॉस मीडिया फोरम आयोजित किया गया. फोरम की बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक शिष्टमंडल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है.

☞ फोरम का उद्घाटन किर्गिजस्तान गणराज्य के राष्ट्रधपति एस जीनबेको ने किया. राष्ट्रसपति ने अपने उद्घाटन भाषण में एसएसीओ के पारप्ड़ारिक विश्वांस, पड़ोसियों के साथ मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध और 'शंघाई भावना'' के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों1 को पूरा करने के लिए एससीओ देशों के मॉस मीडिया संगठनों के महत्वोां को बताया.

फोरम का उद्देश्य:

- फोरम का उद्देश्य एससीओ देशों के बीच मॉस मीडिया के क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत बनाना है.
- फोरम एक साथ संगठन का विजन बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय सूचना क्षेत्र में संगठन छवि को मजबूत बनाने का अनूठा संगठन है.
- फोरम में एससीओ देश(सदस्य देश, पर्यवेक्षक देश, डॉयलग पार्टनर्स) मास मीडिया प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि तथा एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं.

मुख्य तथ्य

- फोरम की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल ने देश में मॉस मीडिया के विकास में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की महत्वथपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला.
- शिष्टनमंडल ने एससीओ साझेदार देशों की विभिन्नज मास मीडिया एजेंसियों, संगठनों तथा संघों के बीच मीडिया सहयोग और श्रेष्ठड व्यकवहारों के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया.
- शिष्टमंडल ने सुझाव दिया कि संयुक्त अंर्तराष्ट्रीय संवाददाता सम्मेलनों के साथ मीडियाकर्मियों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम चलाया जा सकता है. बैठक में फर्जी समाचारों की समस्या से निपटने में एक साथ काम करने के विचार को प्रमुखता से उठाया गया.
- शिष्टममंडल ने नवम्बहर 2019 में गोवा में आयोजित होने वाले भारत अंर्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्वकर्णजयंती समारोह में शामिल होने के लिए एससीओ सदस्य प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया.
- एससीओ के सदस्य देशों ने मीडिया फोरम के प्रस्ताव को स्वीकार किया. जिसमें एससीओ सदस्य देशों के मास मीडिया संगठनों के बीच सफल सहयोग की आवश्यकता व्यक्त की गई है.

पहला एससीओ मीडिया समिट:

- पहला एससीओ मीडिया समिट 01 जून 2018 को बीजिंग में हुआ था. यह आयोजन 'शंघाई भावना' के विकास के नारे के साथ हुआ था. इसमें 16 देशों के 110 मीडिया प्रतिष्ठांनों ने भाग लिया था. इसमें एससीओ सदस्यी देश, पर्यवेक्षक देश तथा डॉयलाग पार्टनर्स शामिल हैं.

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अमेरिका ने ईरानी धातुओं पर प्रतिबंध लगाया

चर्चा में क्यों?

☞ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर ईरानी धातुओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है.

मुख्य तथ्य

- यह कार्यकारी फैसले जारी कर राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम तथा तांबे का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
- इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अमेरिका द्वारा ईरान को स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम और तांबे का निर्यात कर राजस्व जमा करने से रोकना है.
- अमेरिका के अनुसार, ईरान इस पैसे का उपयोग अपने परमाणु कार्यक्रम के अतिरिक्त अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में कर सकता है.
- ईरानी धातुओं का आयात अन्य देशों को भी नहीं करने की बात अमेरिका ने कही है.
- ईरानी राष्ट्रपति हसन रुहानी ने कहा कि उनका देश ओबामा सरकार के समय हुए परमाणु समझौते के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से का पालन बंद कर देगा. ईरान यूरेनियम संवर्धन शुरू करने को लेकर पहले की संधि की नई शर्तों हेतु 60 दिन की समय-सीमा तय करेगा.
- ईरान ने यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साल 2015 की संधि से बाहर निकलने के फैसले के बाद दिया है. राष्ट्रपति हसन रुहानी ने कहा की वह अन्य साझेदारों के मध्य नई शर्तें चाहते हैं.

अमेरिका-ईरान संबंध:

- अमेरिका और ईरान के बीच 1980 से कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है. ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े एकपक्षीय प्रतिबंधों को दोबारा लागू कर दिया जो साल 2015 के समझौते के तहत हटा लिया गया था.
- ईरान के साथ अमेरिका ने 8 मई 2018 को हुए परमाणु समझौते को रद कर दिया था. ईरान को दुनिया में अलग-थलग करने की नीति पर अमेरिका बहुत हद तक सफल भी हुआ है.
- परमाणु करार रद करने पर यूरोपीय संघ के बहुत से देश अमेरिका के विरुद्ध दिखाई दिए थे. ईरान पर अमेरिका ने विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं.
- अमेरिका ने साल 2011 में ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों में संलिप्त व्यवसायी निकायों से संबंध रखने वाली 24 जहाजरानी कंपनियों पर पाबंदी लगा दिया था.
- अमेरिका की ओर से उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम कथित तौर पर परमाणु हथियार विकसित कर रहे ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था.

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश ताइवान बना

चर्चा में क्यों?

☞ ताइवान की संसद ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. ताइवान ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है.

ताइवान की संसद में समलैंगिक विवाह को लेकर यह वोटिंग यहां की संवैधानिक कोर्ट के उस आदेश के दो साल बाद हुई है, जिसमें अदालत ने विवाह से संबंधित मौजूदा कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. यह कानून एक महिला और पुरुष के बीच शादी को ही वैधानिक मानता था.

ताइवान की शीर्ष अदालत:

- ताइवान की शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक ही लिंग के जोड़ों को शादी करने की अनुमति नहीं देना संविधान का उल्लंघन होगा. इस मामले में 14 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक पैनल बनाया गया था जिन्होंने इस पर चर्चा की कि ताइवान का मौजूदा कानून संवैधानिक है या नहीं. अधिकांश रूढ़िवादी सांसदों ने 'नागरिक संघ' कानून के पक्ष में सबसे प्रगति करनेवाला विधेयक को रोकने की कोशिश की.

समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला कानून 24 मई से प्रभावी:

- ताइवान के जजों ने अपने इस आदेश के तहत संसद को इस संबंध में नया कानून बनाने या मौजूदा कानून में ही संशोधन हेतु दो साल का समय दिया था. समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला यह कानून 24 मई 2019 से प्रभावी होगा.
- वे अब सरकारी एजेंसियों में शादी का पंजीकरण करवा सकेंगे. यह फैसला देश के समलैंगिक समुदाय के लोगों की जीत है, जो वर्षों से समान वैवाहिक अधिकारों हेतु मुहिम चला रहे थे.

विधेयक का विरोध:

- अधिकांश रूढ़िवादी सोच वाले सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया था और उन्होंने इस बिल से निजात पाने के लिए मुहिम चलाई थी. इसके साथ ही समलैंगिक विवाह यूनियन को खत्म करने हेतु बिल भी पेश किया था. इसके पक्ष में 66 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में केवल 27 वोट पड़े. ताइपे की संसद के पास भारी बारिश के बीच हजारों की संख्या में एलजीबीटी समुदाय के लोग जमा हुए थे.
- समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला पहला देश नीदरलैंड था. नीदरलैंड को साल 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई. समलैंगिक विवाह नीदरलैंड के अलावा बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका,नार्वे और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में मान्य है.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सिंगापुर संसद ने फेक न्यूज विधेयक पारित किया

चर्चा में क्यों?

☞ सिंगापुर संसद ने हाल ही में फेक न्यूज से निपटने हेतु फेक न्यूज विधेयक पारित कर दिया. यह विधेयक ऑनलाइन मीडिया को सरकार के अनुसार फेक सूचना को सुधारने या हटाने का मौका देगा.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य बिंदु:

- इस विधेयक में अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे 'फेक न्यूज' हटाने का आदेश दे सकते हैं और भारी जुर्माना लगा सकते हैं.
- इस विधेयक में मंत्रियों को यह हक होगा कि वह फेसबुक जैसी सोशल मीडिया वेबसाइटों को उन पोस्ट पर 'चेतावनी' लगाने का आदेश दे सकते हैं जिन्हें अधिकारी फेक मानते हैं.
- आलोचकों का कहना है कि कानून सरकारी अधिकारियों को अपने तरीके से मनचाहा शक्तियां प्रदान करता है. उनका कहना है कि निजी क्षेत्र को फेक और बिना उत्तरदायित्व के बयानों का अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए.
- यह विधेयक 72 सांसदों की सहमति, 09 सांसदों की असहमति से पारित हुआ. खुद को तीन नामांकित सांसदों ने इससे दूर रखा. प्रशासन के मुताबिक, यह विधेयक किसी की विचार, आलोचना, किसी को चिढ़ाने या दुखी करने पर लागू नहीं होता है.
- सिंगापुर सरकार विधेयक के पारित होने से दो मानदंडों के आधार पर यह सुनिश्चित करेगी कि कौन सी खबर को फेक खबर की सूची में डालना है. ये दोनों मानदंड- जब एक फेक विज्ञापन या घोषणा जारी होती है और जब यह कार्रवाई जनहित से संबंधित मानी जाती है.

सजा:

- इस विधेयक के तहत किसी न्यूज में सुधार की मांग करने, सामग्री को हटाने का फैसला या जनहित के विपरीत फेक का प्रचार करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करना शामिल है. इस विधेयक के तहत आदेशों का पालन न करने पर जुर्माना और सजा हो सकती है.
- नए विधेयक के तहत, कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 735000 डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है.
- कंपनियों को कुछ मामलों में सामग्री को हटाने का भी आदेश दिया जा सकता है. वहीं, व्यक्तियों को 10 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है.
- सिंगापुर, जो अपने बड़े स्थानीय मीडिया आउटलेट्स को नियंत्रित करता है. रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर (आरएसएफ) की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर 180 देशों में से 151वें पायदान पर है. इस बिल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दंड प्रस्तावित किये गए हैं. इसका उपयोग विचारो और जानकारी के मुक्त आदान-प्रदान के लिए किया जा सकता है.

स्रोत: द हिंदू

भारत सरकार ने श्रीलंका के विद्रोही संगठन लिट्टे पर लगा प्रतिबंध बढ़ाया

चर्चा में क्यों?

☞ भारत सरकार ने श्रीलंका के विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगे प्रतिबंध को जारी रखा है. केंद्र सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए लिट्टे पर लगे बैन को आगे बढ़ा दिया है.

मुख्य तथ्य

- भारत सरकार के अनुसार, लिट्टे एक हिंसक पृथकतावादी अभियान शुरू कर के उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना चाहते थे.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- केंद्र सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि लिट्टे अभी भी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है.
- लिट्टे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है. सरकार हर दो साल के लिए लिट्टे पर प्रतिबंध लगाता है तथा दो साल बाद उसे बढ़ा दिया जाता है.
- लिट्टे के संघर्ष के दौरान श्रीलंका सरकार के विरुद्ध शांति बहाली के लिए द्वीपीय देश गई भारतीय सेना को वहां बल प्रयोग करना पड़ा था.
- श्रीलंका में भारतीय सेना ने ही लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन और उसके सभी प्रमुख सहयोगियों को मार कर तमिल विद्रोही संगठन का सफाया कर दिया था.
- श्रीलंका में लिट्टे ने भी कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था. लिट्टे फिर से खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में खासकर तमिलनाडू में अपने समर्थन का आधार बढ़ा रहे हैं जो भारत की प्रभुता और अखंडता पर प्रबल विघटनकारी प्रभाव डालेगा.

लिट्टे क्या है?

- लिट्टे एक अलगाववादी संगठन है, जो औपचारिक रूप से उत्तरी श्रीलंका में सक्रिय है. यह संगठन मई 1976 में स्थापित किया गया था.
- यह संगठन एक हिंसक पृथकतावादी अभियान शुरू कर के उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना चाहते थे.

पृष्ठभूमि

- भारत ने सबसे पहले 14 मई 1992 को लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया गया था. उसके बाद से इस प्रतिबंध को बढ़ा दिया जाता है. भारत ने गैरकानूनी गतिविधियों संबंधी अधिनियम के अंतर्गत 14 मई 1992 को पड़ोसी देश श्रीलंका के विद्रोही संगठन लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया था. वहीं इससे पहले ही यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका में भी इस संगठन पर प्रतिबंध था.

स्रोतः द हिंदू , इंडियन एक्सप्रेस

न्यूजीलैंड ने विश्व का पहला 'वेलबीइंग बजट' पेश किया

चर्चा में क्यों?

☞ न्यूजीलैंड सरकार द्वारा विश्व में पहली बार 'वेलबीइंग बजट' पेश किया गया. न्यूजीलैंड सरकार ने इस 'वेलबीइंग बजट' में एक बड़ा हिस्सा बाल गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा रोकने के लिए सुरक्षित रखा है. न्यूजीलैंड में रह रहे बहुतायत लोगों को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाया है जिसके चलते इस प्रकार का बजट लाया गया है.

न्यूजीलैंड के 'वेलबीइंग बजट' की प्रमुख घोषणाएं

- न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था के इतिहास में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य के संकट से निपटने के लिए 1.9 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर (एक न्यूजीलैंड डॉलर 45.57 रुपए के बराबर) की राशि आवंटित की गई है.
- घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 320 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा. बच्चों के कल्याण के लिए एक बिलियन डॉलर से अधिक बजट निर्धारित किया गया है. प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने बच्चों के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया है.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- न्यूजीलैंड के कुल बजट 25.6 बिलियन डॉलर में से 1.2 बिलियन डॉलर स्कूलों, 1 बिलियन डॉलर कीवीरेल, 168 मिलियन डॉलर गन लौटाने की योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं.
- इसके अतिरिक्त वनक्षेत्र में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण पर न्यूजीलैंड के बजट में विशेष ध्यान दिया गया है. न्यूजीलैंड के बजट में पर्यावरण संरक्षण पर 1.13 बिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे.

भूटान का उदहारण

- भूटान विश्व का पहला ऐसा देश है जहां विकास मापने के लिए खुशी को आधार (Happiness Index) बनाया गया है. भूटान में सबसे पहले 1970 में इससे जुड़ा आइडिया पेश किया गया और 2008 में नागरिकों की खुशियां मापने के लिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स लाया गया था. कई और देशों ने भी इसी तरह के प्रयोगों की कोशिश की है, हालांकि, न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जहां सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा खुशी के लिए खर्च किया जाता है.
- न्यूजीलैंड सरकार का कहना है कि 'वेलबीइंग बजट' बजट असमानता की चुनौती से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया है. न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बना गया है जिसने बजट में आर्थिक विकास दर को प्राथमिकता न देते हुए लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी है, इसलिए इसे वेलबीइंग बजट कहा गया है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अनुमान लगाया है कि न्यूजीलैंड के इस बजट के बाद देश अर्थव्यवस्था की विकास दर 2019 में 2.5 प्रतिशत और 2020 में 2.9 प्रतिशत रह सकती है.

स्रोतः द हिंदू

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मई 2019 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है. राष्ट्रपति ने अमेरिका के संचार नेटवर्क को विदेशी दुश्मनों से बचाने के उद्देश्य से यह घोषणा की है.
- यह आदेश अमेरिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं से संबंधित खतरों को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है तथा वाणिज्य मंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरा पैदा करने वाले लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है.

मुख्य तथ्य

- हालांकि कार्यकारी आदेश में किसी भी कंपनी का विशेष रूप से नाम नहीं रखा है, विश्लेषकों के अनुसार यह आदेश चीन की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी हुआवेई के लिए है.
- अमेरिका के अनुसार, चीन हुआवेई के उपकरणों का उपयोग सर्विलांस के लिए कर सकता है. अमेरिका द्वारा लगाये गये इन आरोपों को हुआवेई ने बार-बार खारिज किया है.
- यह आदेश अमेरिका की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत जारी किया गया है.

अमेरिका में आपातकाल

- साल 1976 में एक कानून पारित किया गया था. इस कानून द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी कई राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा चुके हैं.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2009 में स्वाइन फ्लू के प्रकोप के कारण और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9/11 हमले के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था.
- राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान उन विशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जो अमेरिकी संसद के कानून के दायरे में होंगे. अमेरिका में अभी तक 31 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है.

पृष्ठभूमि:

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में एक विधेयक पारित किया था. इस विधयेक में, अमेरिकी सरकार और उसके साथ काम करने वाले लोगों को हुआवेई और चीन की कई अन्य संचार कंपनियों के उत्पादों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था.

स्रोत: द हिंदू

पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ समझौता राशि पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) पाकिस्तान को तीन साल में छह अरब डॉलर (करीब 42 हजार करोड़ रुपये) की सहायता देने जा रहा है. दोनों के बीच इस संबंध में 12 मई 2019 को एक समझौता हुआ है. पाकिस्तान फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है.
- आइएमएफ के अनुसार इस समझौते का मुख्य उद्देश्य घरेलू और बाहरी असंतुलन को कम करने के साथ ही विकास में रुकावट को दूर करना, पारदर्शिता को बढ़ाना और सामाजिक खर्चों में वृद्धि करके मजबूत और अधिक समावेशी विकास हेतु पाकिस्तान को तैयार करना है.

मुख्य तथ्य

- यह समझौता अगले तीन साल के लिए है. आईएमएफ आने वाले तीन सालों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उबारने हेतु 6 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज देगा.
- पाकिस्तान साल 1950 में आईएमएफ का सदस्य बना था. पाकिस्तान आईएमएफ के सदस्य बनने के बाद से अब तक वह 21 बार बेलआउट पैकेज ले चुका है. इस नए पैकेज को मंजूरी मिलने के बाद यह 22वां बेलआउट पैकेज होगा.
- हाल ही में पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज बढ़कर करीब 27.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
- पाकिस्तान इस तरह अब कर्ज हेतु निर्धारित उच्चतम सीमा को भी पार कर चुका है. पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) द्वारा हाल में जारी आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है.
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अप्रैल 2019 में यह अनुमान जारी किया था कि साल 2018-19 में पाकिस्तान का वित्तीय घाटा जीडीपी के 7.9 प्रतिशत तक होगा और साल 2019-20 में यह बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो जाएगा.

  इस समझौते पर 29 अप्रैल से ही अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर चल रहा था. हालांकि, पहले यह समझौता 7 मई तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अंतिम सहमति 12 मई 2019 को ही बन पाई. इस समय पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान को इस हालत से उबारना है.

स्रोत: द हिंदू

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

एनएसएसओ एवं सीएसओ के विलय हेतु मंजूरी

चर्चा में क्यों?

☞ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) में विलय करने का निर्णय लिया है. भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने तथा मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करके अधिक तालमेल बैठाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

मुख्य तथ्य

- नई व्यवस्था के तहत सांख्यिकी शाखा, मुख्य मंत्रालय का एक अभिन्न हिस्सा होगा.
- इस सांख्यिकी शाखा में एनएसओ के साथ घटक के रूप में सीएसओ और एनएसएसओ शामिल होंगे.
- एनएसएसओ की अध्यक्षता सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव करेंगे. इसके विभिन्न विभाग महानिदेशक (डीजी) के जरिये सचिव को रिपोर्ट करेंगे.
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) वृहद आर्थिक आंकड़े जैसे जीडीपी वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करता है. इसका प्रमुख महानिदेशक होता है.

नये विभाग और उनके कार्य

- एनएसएसओ के डेटा प्रसंस्करण विभाग (डीपीडी) का नाम डेटा क्वालिटी एश्योरेंस विभाग (डीक्यूएडी) होगा.
- इस पर सर्वेक्षण के आंकड़ों और गैर - सर्वेक्षण आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने की जिम्मेदारी होगी. गैर - सर्वेक्षण डेटा में आर्थिक गणना और प्रशासनिक आंकड़ों जैसी चीजें शामिल हैं.
- इसी प्रकार, एनएसएसओ का फील्ड ऑपरेशन विभाग (एफओडी) मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय होगा.
- सीएसओ, एनएसएसओ के अन्य सभी विभाग और प्रशासनिक शाखा मंत्रालय के अन्य विभागों के रूप में मौजूद रहेंगे.
- आदेश में राष्ट्रीय संख्यिकी आयोग (एनएससी) को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया. यह देश में सांख्यिकी कार्यों की निगरानी करता है. सरकार ने एक जून 2005 का एनएससी की स्थापना की थी.

CSO

- केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है.
- यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत्त कार्य करता है. इसके कार्यकलापों में राष्ट्रीय लेखा के संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक गणना का आयोजन तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन भी शामिल है.
- केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का प्रमुख महानिदेशक होता है जिसकी सहायतार्थ पांच अपर महानिदेशक होते हैं जो राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, अर्थ-सांख्यिकी प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग और समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग का कार्य देखते हैं.

स्रोतः पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

नाबार्ड ने ग्रामीण स्टार्टअप इकाईयों में 700 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

☞ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने हाल ही में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनियों में इक्विटी निवेश हेतु 700 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी कोष की घोषणा की.

मुख्य तथ्य

- नाबार्ड अभी तक दूसरे कोषों में योगदान करता है. नाबार्ड द्वारा यह पहली बार है कि जब उसने अपना कोष पेश किया है. यह कोष नाबार्ड की अनुषंगी कंपनी नैबवेंचर्स ने पेश किया है.
- इस कोष का नाम 'नैबवेंचर्स फंड -I' है. नाबार्ड द्वारा इसके लिए 500 करोड़ रुपये की पूंजी का प्रस्ताव किया गया है.
- साथ ही ओवर - सब्सक्रिप्शन हेतु 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी का भी विकल्प है.
- यह कोष कृषि , खाद्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करेगा.
- इस कोष से भारत में कृषि , खाद्य एवं ग्रामीण आजीविका जैसे क्षेत्रों में निवेश तंत्र को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.
- नाबार्ड ने अब तक 16 वैकल्पिक निवेश कोष में 273 करोड़ रुपये का योगदान किया है.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) मुम्बई, महाराष्ट्र स्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है.
- इस बैंक को ष्कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में, योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों हेतु मान्यता प्रदान की गयी है.
- नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्धं कराती है.
- शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधि नियम 1981 को लागू करने हेतु संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गयी.
- भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है.

स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

PM-KISAN योजना का विस्तार

चर्चा में क्यों?

☞ हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना सहायता राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

☞ अब इस योजना के लिए भूमि स्वामित्व की सीमा को हटा दिया गया है. पहले इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले निर्धन किसानों को दिया जाता था. अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लगभग 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे.

मुख्य तथ्य

- केंद्र सरकार छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी.
- इस योजना से सरकार खजाने से 75,000 करोड़ रुपये व्यय किया जायेंगे.
- इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है जिन्हें खराब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान होता है.
- यह 6000 रुपये की राशि 2000-2000 हजार की तीन किश्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जायेगी.
- प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इससे सरकारी खजाने पर 87,000 करोड़ रुपये सालाना बोझ पड़ेगा.
- अंतरिम बजट 2019 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना (PM&KISAN) की घोषणा की गयी थी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना-2019

- वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी.
- जिसके तहत सरकार ने दो हेक्टयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ किसानों को तीन किस्तों में 6 हजार रुपये सालाना देने का ऐलान किया था.
- इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिए जायेंगे, यह राशि 500 रुपये प्रति माह होगी. नाबार्ड बैंक के ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण 2015-16 में कृषि से किसान की औसत मासिक आय 3,140 रुपये थी.
- इस प्रकार 500 रुपये प्रति माह से किसान की मासिक आय में 16% की वृद्धि होगी. अब तक इस योजना पर 10,500 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं.

स्रोतः द हिंदू , पीआईबी

आरबीआई ने आरटीजीएस के जरिए लेनदेन की समय सीमा बढ़ाई

चर्चा में क्यों?

☞ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम आदमी को राहत देते हुए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए पैसे भेजने का समयसीमा बढ़ा दिया है. आरबीआई के फैसले के बाद अब ग्राहक 6 बजे तक बैंकों में लेनदेन कर सकेंगे.

☞ यह व्यवस्था 01 जून 2019 से प्रभावी होगी. इससे पहले आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन 4:30 बजे शाम तक किया जा सकता था. फिलहाल 01 जून से पहले आरटीजीएस के जरिए शाम साढ़े चार बजे तक ही मनी ट्रांसफर की सुविधा है.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य बिंदु:

- आरटीजीएस के अतिरिक्त पैसे एक खाते से दूसरे खाते में भेजने का एक अन्य लोकप्रिय माध्यम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) है. इसमें ट्रांसफर के लिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे की सीमा नहीं है.
- आरबीआई ने अधिसूचना में कहा कि उसने आरटीजीएस में ग्राहक लेनदेन हेतु समय को शाम साढे चार बजे से बढ़ाकर 6 बजे करने का फैसला किया है.

आरटीजीएस क्या है?

- आरटीजीएस के तहत व्यक्तिगत खाताधाकों या समूह में ग्राहकों को पैसा भेजने की सुविधा मिलती है.
- आरटीजीएस सिस्टम के तहत मनी ट्रांसफर का काम तुरंत होता है. आरटीजीएस का उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि के हस्तांतरण के लिए होता है.
- गौरतलब है, आरटीजीएस के जरिए न्यूनतम 02 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं जबकि अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है.
- आरटीजीएस सबसे तेज मनी ट्रांसफर सेवा है. आरटीजीएस का उपयोग बैंक से या नेटबैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है.

आरटीजीएस, एनईएफटी से कितना अलग है?

- आरटीजीएस यह फंड ट्रांसफर के एक अन्य तरीके एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) से अलग होता है. एनईएफटी के तहत फंड ट्रांसफर एक निर्धारित समय पर ही होता है. जबकि आरटीजीएस के तहत फंड को तत्काल ट्रांसफर करने के लिए प्रक्रिया में लगा दिया जाता है.

स्रोत: द हिंदू

डिजिटल भुगतान पर नंदन नीलेकणि पैनल ने आरबीआई को रिपोर्ट सौंपी

चर्चा में क्यों?

☞ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने डिजिटल भुगतान पर अपनी रिपोर्ट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सौंप दी है. नीलेकणि के अतिरिक्त आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एच.आर. खान और पूर्व इस्पात सचिव अरुणा शर्मा भी इस पांच सदस्यीय पैनल में थे.

समिति का मुख्य उद्देश्य

- इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटलीकरण के जरिए वित्तीय समावेशन लाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर परामर्श देना था.
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अब समिति की सिफारिशों की जांच करेगा और जरूरत के अनुसार क्रियान्वयन के लिये अपने भुगतान प्रणाली दृष्टिकोण 2021 में शामिल करेगा.
- यह समिति वित्तीय समावेशन में डिजिटल भुगतान के वर्तमान स्तर का भी आकलन करेगी.
- समिति डिजिटल भुगतान में तेजी लाकर अर्थव्यवस्था के डिजिटीकरण और वित्तीय समावेशन में तेजी लाने हेतु अपनाई जा सकने वाली विश्व भर की सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करेगी.
- यह समिति डिजिटल भुगतान की सुरक्षा मजबूत करने के उपाय भी सुझाएगी.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पृष्ठभूमि

- आरबीआई ने 08 जनवरी 2019 को नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था. इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि को इस समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया था. नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में समिति को 90 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी. नंदन नीलेकणि को ही देश में आधार को लागू कराने का महत्वपूर्ण श्रेय जाता है. वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के भी अध्यक्ष रह चुके हैं.

स्रोतः द हिंदू

3 से 7 जून तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जायेगाः आरबीआई

चर्चा में क्यों?

☞ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 जून से 7 जून, 2019 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह-2019 मनाये जाने की घोषणा की गई है. वर्ष-2019 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का विषय है - "किसान और वे किस प्रकार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं." इस सप्ताह के दौरान देश के किसानों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की जायेगी तथा उन्हें विभिन्न वित्तीय पहलुओं से अवगत कराया जायेगा.

आरबीआई साक्षरता सप्ताह-2019

- भारतीय रिजर्व बैंक-2019 3 जून से 7 जून 2019 तक मनाया जायेगा. इसमें पोस्टर, वीडियो, फिल्मों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी.
- वित्तीय जागरुकता सन्देश में 11 संस्थाओं/उत्पाद तदर्थ वित्तीय जागरूकता संदेश हैं जैसे खाता खोलते समय प्रस्तुत कराए जाने वाले दस्तावेज (केवाईसी), बजटिंग, बचत और जिम्मेदाराना उधार का महत्व, ऋण समय पर चुकाकर अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना, आपके दरवाजे पर या पास में बैंकिंग, बैंक और बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक विप्रेषणों का उपयोग, केवल पंजीकृत संस्थाओं में ही पैसे का निवेश करना आदि.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने पाँच लक्ष्य समूहों अर्थात किसानों, लघु उद्यमियों , स्कूली बच्चों , स्वयं सहायता समूहों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सामग्री विकसित की है जिसका उपयोग प्रशिक्षुओं द्वारा वित्तीय साक्षारता कार्यकर्मों में किया जा सकता है.
- दो पोस्टरों - यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) और 99रु (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा) में डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में इन नई धारणाओं का वर्णन किया है.
- आरबीआई की सभी बुकलेट सभी 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं और इन्हें 'डाउनलोड' टैब पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है.

स्रोतः इकोनॉमिक टाइम्स

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से जुड़ेगा एमसीए 21 पोर्टल

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्र सरकार एमसीए 21 पोर्टल को कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जोड़ने की तैयारी कर रही है. सरकार ऐसा कर के नियमों के अनुपालन को और अधिक आसान बनाना तथा नियमों का सामान्य प्रवर्तन निरंतर स्वचालित आधार पर करना चाहता है.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

एमसीए 21 क्या है?

- एमसीए 21 एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है. कंपनियों के बारे में सभी सूचनाएं इसी पोर्टल के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है. इसके जरिए मंत्रालय विनियामकों, कंपनियों और निवेशकों सहित सभी पक्षों तक सूचना का प्रसार करता है. इसका एक मात्र उद्देश्य हित धारकों की डाटाबेस तक पहुंच को सुविधा जनक बनाना है, जो उनके लिए अपना कारोबार और बढ़ाने हेतु अत्यबधिक महत्वहपूर्ण होगा.

मुख्य बिंदु:

- मंत्रालय की योजना है कि यह पोर्टल का तीसरा संस्करण लगभग एक साल में लागू किया जाएगा. इस दौरान एमसीए 21 में कृत्रिम मेधा को शामिल करने की मंत्रालय की कोशिश होगी.
- इसके जरिए सभी फॉर्मों को युक्तिसंगत बनाने एवं डेटाबेस को आपस में जोड़ने की योजना है ताकि प्रवर्तन गतिविधियां स्वत: आधार पर किसी भी समय में जारी रह सकें.
- नई व्यवस्था के लागू होने के बाद संबंधित कंपनी को संज्ञेय जानकारी बार-बार नहीं भरनी पड़ेगी. सिस्टम के डेटाबेस से जुड़ने के बाद सप्ताह में 24 घंटे आटो स्वचालित आधार पर सारी प्रक्रिया पूरी होने लग जाएंगी.

पृष्ठभूमि:

- यह पोर्टल साल 2006 में लॉन्च हुआ था. केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साल 2019 की शुरुआत में इसे अपग्रेड करने के सेवा प्रदाताओं से निविदाएं मांगी गई थीं. टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने ई गवर्नेंस के पहले चरण का काम पूरा किया था, जबकि दूसरे चरण का काम इंफोसिस कर रही है. इंफोसिस ने जनवरी 2013 से दूसरे चरण का काम शुरू किया था, इसके जुलाई 2021 तक पूरा होने की संभावना है.

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की

चर्चा में क्यों?

☞ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में अपनी क्रेडिट पॉलिसी जारी की.

मुख्य तथ्य

- इसमें आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की घोषणा की. आरबीआई ने इस तरह लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है.
- अब रेपो रेट 6 फीसदी से घटकर 5.75 फीसदी हो गई है. यह रेपो रेट पिछले 9 साल में सबसे कम है.
- रेपो रेट में कमी से सभी तरह के लोन सस्ते होंगे. एनईएफटी (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) से पैसे ट्रांसफर करने पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा.

रेपो रेट क्या है?

- आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर दी है. इस कटौती के साथ ही अब आरबीआई देश के बैंकों को 5.75 प्रतिशत की दर पर कर्ज उपलब्ध कराएगा.
- रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है. जब भी बैंकों के पास फंड की कमी होती है, तो वे इसकी भरपाई करने के लिए आरबीआई से पैसे लेते हैं.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- आरबीआई की तरफ से दिया जाने वाला यह लोन एक फिक्स्ड रेट पर मिलता है. यही रेट रेपो रेट कहलाता है.

रिवर्स रेपो रेट में कटौती:

- आरबीआई द्वारा पॉलिसी में रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव किया गया है. रिवर्स रेपो रेट 0.25 फीसदी घटाकर 5.50 फीसदी कर दिया गया है.
- यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है.
- रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है.
- बाजार में जब भी बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमे उसके पास जमा करा दे.

अन्य बदलाव

- आरबीआई की ओर से मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) में 0.25 फीसदी की कटौती की है. अब एमएसएफ 6.25 फीसदी से घटकर 6 फीसदी हो गया है. एमएसएफ वह न्यूनतम दर है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को ब्याज पर ऋण देती है.
- आरबीआई द्वारा बैंक रेट में भी 0.25 फीसदी की कटौती की गयी है. अब बैंक रेट 6.25 फीसदी से घटकर 6 फीसदी हो गया है. बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंको को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है.
- सीआरआर को 4 फीसदी पर ही रखा गया है. देश में लागू बैंकिंग नियमों के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है. इसे ही नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) कहते हैं.
- आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए महंगाई अनुमान बढ़ाया है. पहली छमाही में सीपीआई (CPI) महंगाई दर के लिए अनुमान 3-3.1 प्रतिशत रखा गया है. वहीं, दूसरी छमाही के लिए महंगाई दर का अनुमान 3.4-3.7 प्रतिशत रखा गया है.
- इससे पहले फरवरी और अप्रैल की पॉलिसी में भी आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की गई थी. आरबीआई द्वारा अब तक तीन पॉलिसी में 0.75 फीसदी की कटौती की जा चुकी है.

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं स्वास्थ्य

अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

☞ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में 'अभ्यास' ड्रोन का सफल परीक्षण किया. परीक्षण के समय अभ्यास ड्रोन को विभिन्न राडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम द्वारा ट्रैक किया गया था और सही तरीके से नेविगेशन मोड में रखा गया था.

☞ अभ्यास ड्रोन को एक ऑटो पायलट की मदद से स्वतंत्र उड़ान हेतु डिजाइन किया गया है. इसके नेविगेशन के लिए देश में ही विकसित माइक्रो-इलेक्ट्रोमेकैनिकल सिस्टम (एमईएमएस) आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया गया है.

अभ्यास कैसे काम करता है?

- अभ्यास ड्रोन एक छोटे गैस टरबाइन इंजन पर काम करता है. यह एमईएमएस नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है. डीआरडीओ के अनुसार यह एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती देगा.
- इसको उड़ान भरने के लिए किसी बाहरी चीज के मदद की आवश्यकता नहीं होती है. इस प्रणाली को सिमुलेशन के अनुसार प्रदर्शित किया गया है और लागत को ध्यान में रखते हुए मिशन की जरूरत को पूरा करने के लिए अभ्यास की क्षमता को दिखाया गया है.
- इस ड्रोन का इस्तेमाल अलग-अलग तरीके की मिसाइल और एयरक्राफ्टस का पता लगाने के लिए हो सकता है. अभ्यास ड्रोन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ऑटोपायलट की मदद से अपने टारगेट पर आसानी से निशाना लगा सकता है.

अभ्यास का पहला टेस्ट

- साल 2012 में अभ्यास को पहली बार लॉन्च किया गया था. अभ्यास ड्रोन की अवधारणा और पूर्व-परियोजना विवरण जनवरी 2013 में तैयार किया गया था.
- अभ्यास की शुरुआती लागत 15 करोड़ रुपये थी. इस ड्रोन का डिजायनिंग इसके लक्ष्य पर आधारित था. लक्ष्य डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई) की ओर से विकसित की गई एक हाई स्पीड ड्रोन प्रणाली है.
- इसके पहले अप्रैल 2019 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर रुस्तम-2 को विकसित किया था. इस ड्रोन का 06 अप्रैल 2019 को परीक्षण किया गया था जो सफल रहा था.

स्रोतः द हिंदू

नासा ने आर्टेमिस-2024 मून मिशन के शेड्यूल की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

☞ नासा द्वारा हाल ही में वर्ष 2024 में लॉन्च किये जाने वाले चंद्र मिशन आर्टेमिस के शेड्यूल की घोषणा की गई. नासा की इस घोषणा के अनुसार इसी मिशन के तहत वर्ष 2024 तक नासा आठ प्रोग्राम भी लॉन्च भी करेगा.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मनुष्य के चंद्रमा तक पहुंचने से पहले वहां एक छोटा स्टेशन भी बनाया जायेगा.

☞ इस मिशन की सहायता से लगभग आधी सदी के बाद फिर से मनुष्य चांद पर जायेगा. दरअसल चंद्रमा पर भेजे गये पहले मनुष्य सहित मिशन का नाम अपोलो था. यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार आर्टेमिस अपोलो की जुड़वां बहन थी.

मुख्य तथ्य

- आर्टेमिस (ARTEMIS) का पूरा नाम - Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon*s Interaction with the Sun है.
- नासा 2020 में चन्द्रमा के लिए आर्टेमिस 1 मिशन भेजगा, इसमें अंतरिक्षयात्री नहीं होंगे.
- इसके बाद आर्टेमिस-2 मिशन भेजा जायेगा, यह 2022 में क्रू के साथ चन्द्रमा की परिक्रमा करेगा.
- तदोपरांत आर्टेमिस-3 मिशन भेजा जायेगा, इस मिशन के द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चन्द्रमा पर भेजा जायेगा, इसमें महिला अंतरिक्षयात्री भी होंगी.
- यह तीनों मिशन सबसे बड़े रॉकेट स्पेस लांच सिस्टम द्वारा लॉन्च किये जायेंगे.
- यह सभी मिशन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा लॉन्च किये जायेंगे. इसी क्रम में गेट-वे का पहला मॉडल तैयार करने के लिए निजी कंपनी मैक्सर का चयन किया गया है.
- पहले तीन मिशनों को अब तक के सबसे बड़े रॉकेट ख्र बोइंग स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) द्वारा लॉन्च किया जायेगा.

नासा

- नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए उत्तरदायी है.
- इसका गठन 29 जुलाई, 1958 को किया गया था. नासा विश्व की अग्रणी अन्तरिक्ष एजेंसी है, 14 सितंबर 2011 को नासा ने घोषणा की कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया है जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होंगे.

स्रोतः द हिंदू

डीआरडीओ ने गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

☞ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 24 मई 2019 को राजस्थान के पोकरण में एक सुखोई लड़ाकू विमान से 500 किलोग्राम श्रेणी के एक गाइडेड बम छोड़ने का सफल परीक्षण किया. यह बम देश में ही विकसित किया गया है.

मुख्य तथ्य

- बम ने उच्च सटीकता के साथ तीस किमी की दूरी पर अपने लक्ष्य को निशाना बनाया. गाइडेड बम ने सफलतापूर्वक रेंज हासिल करते हुए लक्ष्य् पर काफी सटीक निशाना लगाया.
- रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, बम छोड़े जाने के परीक्षण के दौरान मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए थे.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के युद्धक हथियारों को ले जाने में सक्षम है. गाइडेड बम का परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब दो दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में एक सुखोई विमान से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफल परीक्षण किया.
- भारतीय वायुसेना को 500 किलोग्राम श्रेणी वाले गाइडेड बम मिलने से मारक क्षमता में काफी इजाफा होगा. दरअसल, गाइडेड बम को लक्ष्य से काफी पहले दागा जाता है. लड़ाकू विमान से दागे जाने के बाद यह अपने लक्ष्य को तलाश करते हुए हवा में उसकी तरफ आगे बढ़ता है.

हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किया गया परीक्षण:

- डीआरडीओ ने इससे पहले 13 मई 2019 को ओडिशा के परीक्षण केंद्र से 'अभ्यास'- हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (हीट) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया.
- परीक्षण में इसकी निगरानी विभिन्न रडारों और इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रणाली के जरिये की गई. नौसेना और डीआरडीओ ने 17 मई 2019 को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था.
- उल्लेखनीय है कि गाइडेड बम को लक्ष्य से काफी पहले दागा जाता है. फाइटर जेट से दागे जाने के पश्चात यह अपने लक्ष्य को तलाश करते हुए हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ता है.

सुखोई लड़ाकू विमान:

- सुखोई 30 एमकेआई भारतीय वायुसेना का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है. यह बहु-उपयोगी लड़ाकू विमान रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई तथा भारत के हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है. इसी श्रृंखला के सुखोई 30 एमकेके तथा एमके-2 विमानों को चीन तथा बाद में इण्डोनेशिया को बेचा गया था. विमान ने साल 1997 में पहली उड़ान भरी थी.

स्रोत: द हिंदू

सिम्बेक्स-2019 समुद्री युद्ध अभ्यास

चर्चा में क्यों?

- भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स-2019 युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है. यह इस अभ्यास का 26वां संस्करण है. इस अभ्यास का आयोजन 16 मई से 22 मई 2019 के बीच किया जा रहा है.
- इस वार्षिक द्विपक्षीय अभ्याससस की शुरुआत पारंपरिक पनडुब्बीस रोधी अभ्यासों से हुई जो एडवांस्ड एयरर डिफेंस ऑपरेशन्स , एंटी हवाई/सतह लक्ष्यों पर अभ्यायस गोलीबारी, सामरिक अभ्यीस आदि तक पहुंच चुकी है.

उद्देश्य:

- सिम्बॉक्स-19 के लिए भारतीय नौसेना ने आपसी विश्वास को मजबूत बनाने, अंत:पारस्परिकता को बढ़ाने एवं दोनों नौसेनाओं के बीच समान सामुद्रिक चिंताओं के समाधान में अधिक समन्वय के निर्माण करने के उद्देश्य से अपने सबसे बेहतरीन एसिट को तैनात किया है.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सिम्बेक्स-2019:

- भारतीय नौसेना के जहाज कोलकाता और शक्ति के अतिरिक्त लंबी दूरी के सामुद्रिक निगरानी विमान भी सिम्बेंक्स-19 में हिस्सा लेंगे.
- सिंगापुर के पक्ष का प्रतिनिधित्व आरएसएन जहाज इस्टीकड फास्टि और वेलियेंट, सामुद्रिक निगरानी विमान फोकर-50 (एफ-50) और एफ-16 लड़ाकू विमान द्वारा किया जाएगा.
- सिम्बेक्से-19 में भारतीय नौसना के जहाज कोलकाता और शक्ति की दक्षिण एवं पूर्व चीन सागर में दो महीने की तैनाती भी शामिल है, जिसका उद्देश्य पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संवर्द्धित सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामुद्रिक अंत:संपर्कों के जरिए मित्रता सेतु को विस्तारित करना है.
- पीएलए (नौसेना) 70वें वार्षिक समारोहों तथा एडीएमएम-प्लटस एमएसएफटीएक्सर के एक हिस्से के रूप में चीन के किंगडाओ में अंर्तराष्ट्री य बेडा समीक्षा (आईएफआर) में भारतीय नौसेना जहाजों की सहभागिता भारत सरकार की 'पूर्व की ओर देखो' नीति तथा भारतीय नौसेना के 'समुद्रों के जरिए राष्ट्रों को एकजुट करने' के प्रयासों को भी प्रदर्शित करती है.

सिम्बेक्स-19 के हार्बर चरण:

- सिम्बेक्स-19 के हार्बर चरण का संचालन 16 मई से 18 मई 2019 तक हुआ था. इसमें कई विनियोजन सम्मेलन, सिमुलेटर अधारित युद्ध प्रशिक्षण या वार गेमिंग, आरएसएन नौसेना के विख्यात व्यक्तियों से औपचारिक मुलाकात, क्रीड़ा स्पर्धाएं तथा डेक रिसेप्शन ऑन बोर्ड कोलकाता के रूप में शामिल हैं.

सिम्बेक्स-19 का सामुद्रिक चरण:

- सिम्बेक्स-19 का सामुद्रिक चरण दक्षिण चीन सागर में 19 मई से 22 मई 2019 तक निर्धारित है, जिसमें हवाई/सतह लक्ष्यों पर गोलीबारी, एडवांस्ड एरियल ट्रैकिंग, समन्वित लक्ष्य निर्धारण अभ्यास एवं हवाई/सतह परिदृश्यों पर सामरिक अभ्यास शामिल होंगे.

पृष्ठभूमि

- साल 1993 में अपनी शुरुआत से सिम्बेक्स सुनियोजित और संचालनगत जटिलता के साथ आगे बढ़ा रहा है. सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग पहली बार औपचारिक हुआ जब आरएसएन जहाजों ने साल 1994 में भारतीय नौसेना के साथ प्रशिक्षण शुरू किया.

स्रोत: द हिंदू

भारतीय नौसेना ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया

चर्चा में क्यों?

☞ भारतीय नौसेना द्वारा 17 मई 2019 को मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) का सफल परीक्षण किया गया है. रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में यह जानकारी सार्वजनिक की गई है. एमआरएसएएम के सफल परीक्षण से भारतीय नौसेना की युद्ध प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

☞ भारतीय नौसेना के पोत 'कोच्चि 'और 'चेन्नषई ' ने पश्चिमी समुद्र तट पर यह परीक्षण किया गया. इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना, डीआरडीओ और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है.

मुख्य तथ्य

- भारतीय नौसेना द्वारा किये गये परीक्षण के दौरान दो वॉर शिप की मिसाइलों को एक शिप से ऑपरेट किया गया.
- इन्हें अलग-अलग टारगेट पर साधा गया जिनकी रेंज भी अलग-अलग रखी गई थी.
- परीक्षण में पाया गया कि यह मिसाइल लड़ाकू विमान को भी नष्ट कर सकती हैं तथा सटीक वार करने में सक्षम हैं.
- वर्तमान में इन मिसाइलों की सुविधा केवल चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास की है.
- डीआरडीओ ने इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर इस मिसाइल का विकास किया है. भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने एमआरएसएएम का निर्माण किया है.
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने एमआरएसएएम के निर्माण एवं विकास में मुख्य भूमिका निभाई है.
- भविष्य में इस मिसाइल को भारत के सभी समुद्री युद्धपोतों में इस्तेमाल किया जा सकता है.
- मध्यम दूरी तक मार कर सकने वाली यह मिसाइलें 70 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती हैं.

स्रोतः द हिंदू

भारतीय वायुसेना को मिला पहला अपाचे हेलीकॉप्टर

चर्चा में क्यों?

☞ भारतीय वायुसेना को अपना पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे गार्जियन मिल गया है. इस हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका के एरिजोना में हुआ है. भारतीय वायुसेना को इससे पहले चिनूक हैवीलिफ्ट हेलीकॉप्टर मिल चुका है.

अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत

- बोइंग एएच-64 ई अपाचे को विश्व का सबसे ताकतवर और खतरनाक हेलीकॉप्टर माना जाता है. इस हेलीकॉप्टर से सटीक हमले किये जा सकते हैं.
- इस हेलीकॉप्टर में सटीक मार करने तथा जमीन से उत्पन्न खतरों के बीच प्रतिकूल हवाईक्षेत्र में परिचालित होने की क्षमता है. हेलीकॉप्टर के दोनों ओर 30 एमएम की दो गन लगी हैं.
- यह हेलिकॉप्टर लगभग 293 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है. इस हेलिकॉप्टर में चालक दल के दो सदस्य होते हैं.
- यह हेलिकॉप्टर लगभग 21000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है. इस हेलीकॉप्टर को रडार से पकड़ना बहुत ही मुश्किल है.
- इस हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 एमएम की 1,200 गोलियां भरी जा सकती हैं. इसके अतिरिक्त इस हेलीकॉप्टर में हेलिफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलें लगी हैं.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम या किसी भी स्थिति में दुश्मन पर हमला कर सकता है.
- भारत की जरूरत के हिसाब से इस हेलीकॉप्टर में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. इसमें लगी अचूक मिसाइलें और रॉकेट जमीन पर मौजूद दुश्मनों की फौज तथा सैन्य दस्तों को तबाह करने की क्षमता रखती हैं.

महत्व

- अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल करना भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेडेघ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी.
- अमेरिका के अलावा कई देश अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं. यह हेलीकॉप्टर इजरायल, मिस्त्र और नीदरलैंड की सेनाओं के पास भी है.
- इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना के एडवांस अटैक हेलिकॉप्टर प्रोग्राम हेतु बनाया गया था. इसने पहली उड़ान साल 1975 में भरी थी. इसे साल 1986 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था. यह विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला अटैक हेलीकॉप्टर है.

स्रोतः द हिंदू

केरल में खतरनाक निपाह वायरस की फिर पुष्टि

चर्चा में क्यों?

- केरल में एक बार फिर खतरनाक निपाह वायरस का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है. केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने राज्य में निपाह वायरस के पहले मामले की पुष्टि की है.
- दरअसल, केरल के 23 साल के एक छात्र को निपाह वायरस से संक्रमित होने के शक में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. निपाह वायरस की पुष्टि पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) की रिपोर्ट में हुई है.

निपाह वायरस का प्रकोपः

- केरल में साल 2018 में ही निपाह वायरस से कोझिकोड और मलप्पुरम जिले में करीब 16 जानें जा चुकी हैं. निपाह वायरस बहुत ही खतरनाक है.
- दरअसल निपाह वायरस स्वाभाविक रूप से कशेरुकी जानवरों से मनुष्यों तक फैलती है.
- यह रोग साल 2001 में और फिर साल 2007 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी सामने आया था. पहली बार भारत में टेरोपस गिगेंटस चमगादड़ में इस वायरस का पता चला था.

डब्लूएचओ के अनुसार, निपाह वायरसः

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के अनुसार, निपाह वायरस एक नई उभरती बीमारी है. इसे 'निपाह वायरस एन्सेफलाइटिस' भी कहा जाता है.
- निपाह वायरस एक तरह का दिमागी बुखार है. इसका संक्रमण तेजी से फैलता है. यह संक्रमण होने के 48 घंटे के भीतर व्यक्ति को कोमा में पहुंचा देता है.

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

एम्स में भारत का पहला मल्टी-स्क्लेरोसिस क्लिनिक खोला जायेगा

चर्चा में क्यों?

☞ एम्स-दिल्ली द्वारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बेहतर निदान और उपचार के लिये देश का पहला मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लिनिक खोला जायेगा. एम्स द्वारा यह क्लिनिक जून के दूसरे सप्ताह में खोला जायेगा.

☞ भारत में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, बड़े पैमाने पर इस महामारी के संबंध में अध्ययन करने, समर्पित मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लीनिक खोलने, इष्टतम पुनर्वास आदि जैसी अन्य सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है.

मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है?

- मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा रोग है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही माइलिन (वसायुक्त पदार्थ जो तंत्रिका तंतुओं के चारों और स्थित होता है तथा आवरण के रूप में काम करता है), तंत्रिका तंतुओं तथा शरीर में माइलिन का निर्माण करने वाली विशेष कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती है.
- इसके लक्षण सामान्य होते हैं, इसलिये लोग अक्सर इस बीमारी को जल्दी पहचान नहीं पाते हैं. इस बीमारी के निदान में लंबा समय लग जाता है.
- यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और दृष्टि से संबंधित नसों को प्रभावित करती है.
- इसके अन्य लक्षणों में शामिल हैं - मांसपेशियों की कमजोरी और अकड़न, मूत्राशय की समस्याएँ: मरीज को मूत्राशय में समस्या महसूस होती है, बार-बार या अचानक पेशाब करने की आवश्यकता होती है, मूत्राशय पर नियंत्रण का खत्म हो जाना इस बीमारी का प्रारंभिक संकेत है; रीढ़ की हड्डी में क्षतिग्रस्त तंत्रिका तंतु, धुंधली या दोहरी दृष्टि की समस्या, भावनात्मक परिवर्तन और अवसाद, संज्ञानात्मक (निर्णय लेने में समस्या) नुकसान.

मल्टी-स्क्लेरोसिस क्लिनिक की आवश्यकता

- यह बीमारी पश्चिम के देशों में अधिक प्रचलित रही है, लेकिन हाल के दिनों में भारत में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं.
- 20-40 वर्ष आयु वर्ग के वयस्क, विशेष रूप से महिलाएँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस की चपेट में आती हैं.
- भारत में लोगों को इस बीमारी से बचाने, रोग को फैलने से रोकने तथा इस महामारी के संबंध में अध्ययन करने, समर्पित मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लीनिक खोलने की अत्यधिक आवश्यकता है.

स्रोत: द हिंदू , टाइम्स ऑफ इंडिया

भारतीय वायुसेना के एएन-32 विमान को जेट्रोफा बायो-फ्यूल उपयोग करने की मंजूरी दी गई

चर्चा में क्यों?

☞ भारतीय वायुसेना के दुर्जेय विमान, जो कि रूस निर्मित एएन-32 विमान है, को 26 मई 2019 को मिश्रित विमानन ईंधन से संचालित करने के लिए औपचारिक रूप से प्रमाणित किया गया. इस मंजूरी के बाद भारतीय वायुसेना के इस विमान में प्रयोग किये जाने वाले मिश्रित ईंधन में 10 प्रतिशत तक स्वदेशी बायो-जेट ईंधन का उपयोग किया जा सकेगा.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

☞ सीएसआईआर-आईआईपी प्रयोगशाला, देहरादून द्वारा वर्ष 2013 में पहली बार स्वदेशी बायो-जेट ईंधन का उत्पादन किया गया था. उस समय व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए इस ईंधन का परीक्षण नहीं हो सका था क्योंकि विमानन क्षेत्र में परीक्षण सुविधाओं का आभाव था.

जेट्रोफा फ्यूल

- जेट्रोफा नामक पौधे से तैयार होने वाले लेट को जेट्रोफा फ्यूल कहा जाता है. इसके व्यावसायिक महत्व के बारे में अनभिज्ञता होने के कारण भारत में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था.
- पिछले कुछ वर्षों से इसका उपयोग बायोडीजल के रूप में होने के कारण यह डीजल, केरोसिन तथा अन्य जलावन के विकल्प के रूप में उभरा है.
- भारत में भी जेट्रोफा का उपयोग किया जा चुका है जिसमें भारतीय रेल दिल्ली से अमृतसर के बीच जेट्रोफा बायोडीजल से चलाई जा चुकी है.
- पिछले वर्ष स्पाइसजेट ने भी जेट्रोफा तेल से देश में पहला बायो-फ्यूल विमान उड़ाया था. चूंकि यह पौधा बंजर और ऊसर जमीन पर उग सकता है इसलिए देश में इसकी उपयोगिता बढ़ी है.
- जेट्रोफा इसके बीज में पाए गए तेल को उच्च गुणवत्ता वाले डीजल ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है. चूंकि जेट्रोफा अखाद्य है इसलिए इसका ईंधन में ही मुख्यत: उपयोग हो सकता है. इसके अलावा सूखे का सामना करने की क्षमता होना, स्वाभाविक रूप से कीट-खरपतवार से लड़ने की क्षमता और एवरेज क्वालिटी की मिट्टी में उग जाना इसे बायो फ्यूल की दुनिया का गेम-चेंजर बनाता है. भारत में खेती के लिए उपलब्ध जमीन में से 20% से अधिक जमीन को उपर्युक्त मानकों के हिसाब से 'जट्रोफा आरक्षित' जमीन कहा जा सकता है.

पृष्ठभूमि

- भारतीय वायुसेना को यह अनुमति पिछले एक वर्ष में किये गये विभिन्न परीक्षणों के बाद मिली है. वायुसेना ने हरित विमानन ईंधन के लिए कई परीक्षण किये हैं. इन परीक्षणों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा गया है. मौजूदा अनुमोदन से स्वदेशी बायो-जेट ईंधन के उपयोग के लिए किए गये विभिन्न परीक्षणों को स्वीकृति मिली है. यह ईंधन जेट्रोफा तेल से बना है जिसे छत्तीसगढ़ बायोडीजल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया और फिर इसे सीएसआईआर-आईआईपी, देहरादून में प्रसंस्कृत किया गया है.

स्रोत: द हिंदू

RISAT-2B का सफल प्रक्षेपण

चर्चा में क्यों?

☞ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 22 मई 2019 को पीएसएलवी-सी46 के जरिए 'रीसैट -2बी' (RISAT-2B) रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है. यह इस सीरीज का चौथा सैटेलाइट है. यह सैटेलाइट दिन, रात, घने बादल और बारिश में भी निगरानी रख सकता है.

☞ प्रक्षेपण के दौरान रॉकेट अपने साथ 615 किलोग्राम रीसैट -2बी को ले गया है. रीसैट-2 के करीब सात साल बाद रीसैट-2बी को प्रक्षेपित किया गया है. प्रक्षेपण के करीब 15 मिनट बाद रॉकेट 'रीसैट -2बी' को लगभग 555 किलोमीटर दूर वाली कक्षा में स्थापित कर दिया. यह पहली बार है जब भारत ने अंतरिक्ष में इस तरह से स्वदेशी तकनीक लॉन्च की हैं.

मुख्य तथ्य

- रीसैट -2बी का उपयोग कृषि क्षेत्र, वन विज्ञान और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा. इसके साथ ही देश की

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा राहत कार्य में लगे लोगों सुरक्षाबलों को रीसैट -2बी से काफी मदद मिलेगी.

- इससे भारतीय सुरक्षा बलों को बॉर्डर पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी. इस सैटेलाइट से भारतीय सुरक्षा बलों की सभी मौसम में निगरानी की क्षमता बढ़ जाएगी.
- इस सैटेलाइट से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी. यह सैटेलाइट धरती पर मौजूद किसी बिल्डिंग या किसी वस्तु की तस्वीरें दिनभर में ही दो से तीन बार ले सकती है.
- इस सैटेलाइट के जरिए जमीन पर तीन फीट की ऊंचाई तक की बेहतरीन तस्वीरें ली जा सकती हैं. यह सैटेलाइट सीमाओं पर घुसपैठ रोकने में भी सुरक्षाबलों को सहायता प्रदान करेगा.
- यह हर मौसम में चाहे रात, बादल हो या बारिश, ऑब्जेक्ट की सटीक लोकेशन और उसकी तस्वीरें जारी करेगा.

पृष्ठभूमि:

- रीसैट (RISAT) सीरीज का पहला सैटेलाइट 20 अप्रैल 2009 को लॉन्च किया गया था. 300 किलोग्राम का सैटेलाइट X-बैंड सिंथेटिक एपर्चर का इस्तेमाल करता है. इस सैटेलाइट को इजरायल ऐरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया था.

स्रोत: द हिंदू

अल्टिमा थुले पर मिले पानी की मौजूदगी के सबूत: नासा

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को हाल ही में अल्टिमा थूले की सतह पर मेथनॉल, पानी की जमी बर्फ, और कार्बनिक अणुओं के एक अद्वितीय मिश्रण का सबूत मिला है. मानव जाति द्वारा खोजी गई अब तक की यह सबसे दूर की दुनिया है.
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अल्टिमा थुले की पहला प्रोफाइल अपने साइंस जर्नल में प्रकाशित किया है. इसके तहत अंतरिक्ष की जटिल दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी मिली है. शोधकर्ता अल्टिमा थूले की सतह की विशेषताओं का भी अध्ययन कर रहे हैं. साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक, शोध कर रही टीम को अल्टिमा थूले की सतह पर मेथनॉल, पानी की बर्फ और कार्बनिक अणुओं के सबूत मिले हैं.

कूइपर बेल्ट में स्थित ऑब्जेक्ट:

- कूइपर बेल्ट (अंतरिक्ष का सबसे दूर की सतह) में स्थित ऑब्जेक्ट 2014 एमयू 69 नामक पिंड को अल्टिमा थुले नाम दिया गया है. नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने 2019 में नए साल के मौके पर उड़ान के दौरान इस पिंड का डाटा इकट्ठा किया था. इसके पहले सेट का विश्लेषण करने के बाद अंतरिक्ष की जटिल दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी मिली है.
- इस सेट के विश्लेषण से अल्टिमा थुले के विकास, भूविज्ञान और रचना के बारे में बहुत कुछ खुलासा हुआ है. इसमें इसकी सतह पर खास निशान, पहाड़नुमा आकृतियां और ज्वालामुखी के विस्फोट से बनने वाले गड्ढे भी शामिल हैं. इस पिंड की सतह कूइपर बेल्ट के अन्य पिंडों की तरह ही गहरी लाल है. इसका मुख्य कारण सतह पर कार्बनिक तत्वों की ज्यादा मौजूदगी को माना जा रहा है.

न्यू होराइजन्स

- यह अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था नासा का एक अंतरिक्ष शोध यान है. यह शोध यान सौर मंडल के बाहरी बौने ग्रह प्लूटो के अध्ययन के लिये छोड़ा गया था. इस यान का प्रक्षेपण 19 जनवरी 2006 को किया गया था.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अल्टिमा थुले

- अल्टिमा थुले एक अंतरिक्ष यान द्वारा देखी गई अब तक की सबसे दूर की वस्तु है. अल्टिमा थुले प्लूटो से 1. 6 बिलियन किलोमीटर तथा पृथ्वी से 6.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
- अल्टिमा थुले 4.5 बिलियन साल पहले सौर प्रणाली के उत्पत्ति के संबंध में सूचनाएँ एकत्र करेगा. इससे हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी.

स्रोतः द हिंदू

ब्रह्मोस मिसाइल के हवा से सतह पर मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के वायु से सतह पर मार करने वाले संस्करण का सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया.
- भारतीय वायुसेना के इंजीनियरों ने विमान के सॉफ्टवेयर का विकास किया जबकि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सुधार किये.

मुख्य तथ्य

- हवा से सतह पर मार करने में सक्षम 2.5 टन वजनी मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है. इससे भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ध्वनि के वेग से करीब तीन गुना अधिक 2.8 मैक गति से लक्ष्य को भेदेगी.
- ब्रह्मोस मिसाइल दिन अथवा रात तथा हर मौसम में भारतीय वायुसेना को समुद्र अथवा जमीन पर किसी भी लक्ष्य को सटीक निशाना बनाने की क्षमता प्रदान करता है.
- भारतीय वायुसेना दुनिया की पहली ऐसी वायुसेना बन गयी, जिसने 22 नवंबर 2017 को एक समुद्री लक्ष्य पर वायु से मार करने वाली 2.8 मैक जमीनी प्रहार मिसाइल को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था. आज इस तरह के हथियार का दूसरी बार प्रक्षेपण किया गया.
- भारतीय वायुसेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और एचएएल के समर्पित एवं समन्वित प्रयासों ने ऐसे जटिल कार्यों को हाथ में लेने की देश की क्षमता को साबित कर दिया है.

ब्रह्मोस

- ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट, सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल है. इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है. रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है. यह रूस की पी-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है.

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

डिमेंशिया रोकथाम हेतु नये दिशा-निर्देश जारी

चर्चा में क्यों?

☞ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में डिमेंशिया की समस्या को कम करने तथा बढ़ते रोगियों की संख्या में कमी लाने हेतु नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं. WHO ने कहा है कि आने वाले तीस वर्षों में डिमेंशिया के रोगियों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हो सकती है.

☞ डिमेंशिया के खतरे को कम करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमें प्रमुख रूप से धूम्रपान न करने, नियमित व्यायाम, शराब के सेवन से बचने, वजन को नियंत्रित करने, स्वस्थ आहार लेने तथा रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने की सलाह प्रमुख रूप से दी गई है.

प्रमुख दिशा-निर्देश

- नियमित व्यायाम: डिमेंशिया में गिरावट लाने के लिए सभी वयस्कों को शारीरिक व्यायाम को नियमित रूप से अपनाना चाहिए.
- धूम्रपान का त्याग: डिमेंशिया और अन्य गंभीर रोगों से बचने के लिए तथा डिमेंशिया के खतरे को कम करने के लिए धूम्रपान जितना जल्दी हो सके, छोड़ देना चाहिए.
- स्वास्थ्यवर्धक भोजन: डिमेंशिया के रोगियों तथा उन सभी वयस्कों को जिन्हें इस रोग का खतरा है उन्हें स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही लेना चाहिए. विटामिन बी, ई तथा बैलेंस डाइट लेने से रोग का खतरा कम किया जा सकता है.
- डिप्रेशन से बचें: डब्ल्यूएचओ ने अपने नये दिशा-निर्देशों में कहा है कि लोगों को तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बचना चाहिए ताकि वे आगे चलकर डिमेंशिया से प्रभावित न हों. इसके लिए उन्हें तनाव होने पर अपने साथियों के साथ बात करनी चाहिए.

डब्ल्यूएचओ डिमेंशिया रिपोर्ट का आधार

- डब्ल्यूएचओ के यह दिशा-निर्देश उस अध्ययन पर आधारित हैं जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिये महत्त्वपूर्ण हैं इसके माध्यम से रोगियों में संज्ञानात्मक गिरावट और डिमेंशिया को रोकने में मदद मिल सकती है.
- डब्ल्यूएचनों इस संदर्भ में 'आई सपोर्ट' नामक प्रोग्राम तैयार किया है जो एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके तहत देखभाल से संबंधित समग्र प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन से निपटने तथा स्वयं स्वास्थ्य की देखभाल करने की सलाह के साथ डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल की जाती है.
- डिमेंशिया के लिये जोखिम वाले कारकों में कमी लाना डब्ल्यूएचओ की वैश्विक कार्रवाई योजना में शामिल है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है. इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी. इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है. डब्ल्यू.एच.ओ. संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है. इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी.

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

नासा का पेलोड लेकर जाएगा चंद्रयान-2

चर्चा में क्यों?

☞ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में कहा कि जुलाई में भेजे जाने वाले भारत के दूसरे चंद्र अभियान में 13 पेलोड होंगे और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक उपकरण होगा.

☞ नासा इस मॉड्यूल के जरिए धरती और चांद की दूरी को नापने का कार्य करेगी. इसरो ने चंद्र मिशन के बारे में कहा कि 13 भारतीय पेलोड (ओर्बिटर पर आठ, लैंडर पर तीन और रोवर पर दो पेलोड तथा नासा का एक पैसिव एक्सपेरीमेंट (उपर्कण) होगा.

मुख्य तथ्य

- इस अंतरिक्ष यान का वजन 3.8 टन है. इस यान में तीन मोड्यूल (विशिष्ट हिस्से) ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) हैं.
- चंद्रयान- 2 को 06 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है. ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर उसका चक्कर लगाएगा, जबकि लैंडर (विक्रम) चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आसानी से उतरेगा और रोवर (प्रज्ञान) अपनी जगह पर प्रयोग करेगा.
- चंद्रयान-2 मिशन के सफल होने पर रूस, अमेरिका, चीन और इजरायल के बाद भारत चांद पर अपना यान उतारने वाला पांचवां देश बन जाएगा.
- रोवर का वजन 20 से 30 किलो के बीच होगा. यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा. रोवर चन्द्रमा की सतह पर पहियों के सहारे चलेगा.
- यह मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा तथा उनका रासायनिक विश्लेषण करेगा. रोवर डाटा को ऊपर ऑर्बिटर के पास भेज देगा जहां से इसे पृथ्वी के स्टेशन पर भेज दिया जायेगा.

चंद्रयान- 2 :

- भारत का चंद्रयान -1 के बाद दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान चंद्रयान-2 है. इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) ने विकसित किया है. इस अभियान को जीएसएलवी मार्क 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपण करने की योजना है. इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी (रोसकोसमोस) के प्रतिनिधियों ने 12 नवम्बर 2007 को चंद्रयान-2 परियोजना पर साथ काम करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
- इसरो के अनुसार इस अभियान में जीएसएलवी मार्क 3 प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया जाएगा. रोवर चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा. वैज्ञानिक प्रयोग के लिए लैंडर और ऑर्बिट पर भी उपकरण लगाए गए हैं. इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम रखा गया है. इसमें चार पेलोड हैं. यह पंद्रह दिनों तक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा.

स्रोत: द हिंदू

नासा अध्ययन:150 फुट सिकुड़ गया है चांद

चर्चा में क्यों?

☞ नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) द्वारा किये गये हालिया अध्ययन के अनुसार चांद का

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आकार लगातार सिकुड़ रहा है. नासा के लूनर रीकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) द्वारा ली गई 12,000 से अधिक तस्वीरों के विश्लेषण से यह जानकारी सामने आई है. इस अध्ययन में यह पाया गया है कि चंद्रमा का आकार विभिन्न कारणों से लगातार सिकुड़ रहा है.

☞ लूनर रीकॉनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा की 3डी तस्वीरें ली गई हैं. इन तस्वीरों में चंद्रमा में हुए परिवर्तनों को देखा जा सकता है. वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया तथा चंद्रमा की सतह पर हो रहे बदलावों का अध्ययन करके यह रिपोर्ट जारी की.

मुख्य तथ्य

- नासा द्वारा अध्ययन में यह देखा गया कि चंद्रमा के उत्तरी ध्रूव के पास चंद्र बेसिन 'मारे फ्रिगोरिस' में दरार पैदा हो रही है और जो अपनी जगह से खिसक भी रही है.
- नासा का मानना है कि ऊर्जा खोने की प्रक्रिया के कारण ही चंद्रमा पिछले लार्खों वर्षों से धीरे धीरे लगभग 150 फुट तक सिकुड़ गया है.
- यह भी संभावना जताई गई है कि लाखों साल पहले हुई भूगर्भीय गतिविधियां आज भी जारी हैं.
- चंद्रमा पर आने वाले भूकम्पों के कारण चंद्रमा को सबसे अधिक हानि होती है जिसके कारण यह धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है.
- पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर कोई टैक्टोनिक प्लेट्स नहीं है तथा चंद्रमा का श्मारे फ्रिगोरिसश भूवैज्ञानिक नजरिये से मृत स्थल माना जाता है इसके बावजूद चंद्रमा पर टैक्टोनिक गतिविधियां हो रही हैं.
- वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा में ऐसी गतिविधि ऊर्जा खोने की प्रक्रिया में 4.5 अरब साल पहले हुई थी.
- ऊर्जा खोने पर चंद्रमा की सतह सिकुड़ती है और फिर सीधी होती है लेकिन यह अपनी पहली अवस्था में न आकर थोड़ी सिकुड़ी हुई रह जाती है, यही प्रक्रिया चंद्रमा पर भूकंप पैदा करती है.

लूनर रीकॉनिसेंस ऑर्बिटर (Lunar Reconnaissance Orbiter) (LRO)

- लूनर रीकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जो वर्तमान में एक धरुवीय मानचित्रण कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है.
- एलआरओ द्वारा एकत्रित की गई जानकारी चंद्रमा पर मानव के भविष्य को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है.
- एलआरओ द्वारा किये जा रहे मैपिंग से चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यानों को भी सहायता मिल रही है.
- अन्तरिक्ष यानों को सुरक्षित लैंडिंग की सतह के बारे में सटीक जानकरी मिल जाती है. नासा द्वारा इसे 18 जून 2009 को लॉन्च किया गया था.
- यह चंद्रमा की 3डी तस्वीरें पृथ्वी पर भेजता है. इसके द्वारा भेजी गई पहली तस्वीर 2 जुलाई 2009 को प्रकाशित की गई थी.

स्रोतः द हिंदू

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवसः11 मई

चर्चा में क्यों?

☞ भारत में 11 मई 2019 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया. यह दिवस भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य तथ्य

- इस दिन राष्ट्र गर्व के साथ-साथ अपने वैज्ञानिको की उपलब्धियों को भी याद किया जाता है.
- इस दिवस को तकनीकी रचनात्मकता, वैज्ञानिक जांच, उद्योग और विज्ञान के एकीकरण में किये गये प्रयास के प्रतीक माना जाता है.
- भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने के बाद भी विश्व के कई देशों से पिछड़ा हुआ. भारत को अभी भी बहुत-से लक्ष्य तय करने होंगे.
- इसीलिए '11 मई' का दिन प्रौद्योगिकी के हिसाब से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार:

- भारत के राष्ट्रपति इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी प्रदान करते हैं. यह पुरस्कार इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस:

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत साल 1998 में हुए पोखरण परमाणु टेस्ट से हुई थी.
- भारत ने साल 1998 में '11 मई' के दिन ही अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था.
- यह परमाणु परीक्षण पोखरण, राजस्थान में किया गया था. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है.

स्रोत: द हिंदू

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस:22 मई

चर्चा में क्यों?

☞ विश्व भर में 22 मई 2019 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया. जैव-विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव-विविधता का महत्व देखते हुए ही अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया.

☞ जैव विविधता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीव.जंतु और पेड़-पौधों का अस्तित्व धरती पर एक साथ बनाए रखने से होता है. जैव विविधता की कमी से बाढ़, सूखा और तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ जाता है. पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने तथा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में भी जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस-2019 का विषय:

- अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस-2019 का विषय "हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य एवं हमारा स्वास्थ्य (Our Biodiversity] Our Food] Our Health)" हैं.
- इस वर्ष की थीम भी इसलिए जैव विविधता को भोजन की उपलब्ध विविधता और स्वास्थ्य चिताओं के उद्देश्य में राखी गयी है.
- इस थीम का मुख्य उद्देश्य हमारी खाद्य प्रणाली में बदलाव और मानव स्वास्थ्य में सुधार के उत्प्रेरक रूप में भोजन व स्वास्थ्य के आधार के रूप में जैव विविधता को रखना हैं.

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य

- अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है, जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके.
- इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला शिल्प, संगीत, वस्त्र-भोजन, औषधीय पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव-विविधता के महत्व और उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है.

पृष्ठभूमि:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को 55/201 प्रस्ताव पारित करके 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविध ता दिवस के रूप में मनाये जाने का संकल्प लिया. इस दिवस का मुख्य उद्देश्य 22 मई 1992 को पारित किये गये नैरोबी एक्ट का पालन करना तथा इस संबंध में लोगों को जागरुक करना है. अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अधिकारिक घोषणा से पहले 29 दिसंबर को मनाया जाता था.

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

गंगा बेसिन क्षेत्र में रूद्राक्ष के वृक्ष लगाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

☞ केंद्र सरकार ने हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किये. उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में रूद्राक्ष के वृक्ष लगाने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, एचसीएल फाउंडेशन और इन्टेक के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है.

लक्ष्य:

- इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में स्था नीय समुदाय और अन्यइ हितधारकों के सहयोग से 10,000 रूद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
- यह उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आय को भी बढ़ावा देने में भी मदद करेगा. इससे लोगों को रोजगार में बढ़ावा मिलेगा ।

नमामि गंगे:

- नमामि गंगे मिशन जून 2014 में शुरू किया गया था. नमामि गंगे एक व्यापक पहल है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण उन्मूलन और संरक्षण के उद्देश्य पर पहले से चल रहे और वर्तमान में शुरू किए गए प्रयासों को एकीकृत करती है.
- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नदी की सतही गंदगी की सफाई सीवरेज उपचार हेतु बुनियादी ढांचे, नदी तट विकास, जैव विविधता, वनीकरण और जन जागरूकता जैसी प्रमुख गतिविधियां सम्मिलित हैं.

नमामि गंगे मिशन का उद्देश्य:

- नमामि गंगे मिशन का मुख्य उद्देश्य गंगा के आसपास के 97 शहरों और 4,465 गांवों में स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र हेतु व्यापक और स्थायी समाधान उपलब्धा कराना है.
- इसके लिए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल से बहुत कुछ हासिल हो सकेगा.
- नमामि गंगे मिशन न सिर्फ नई आधारिक संरचना (इंफ्रास्ट्रक्टर) का निर्माण कर रहा है, बल्कि पुरानी और खराब हो चुके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) का रख-रखाव, संचालन को सुनिश्चित भी करता है.
- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी में पर्यावरण विनियमन और जल की विशिष्ट गुण की निगरानी रखना है.

नमामि गंगे के तहत 28,377 करोड़ रुपए की कुल लागत से 289 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 87 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं. 23,158.93 करोड़ रुपए की लागत से 151 सीवरेज प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिनमें गंगा के मुख्य धारा पर 112 और सहायक नदियों पर 39 प्रोजेक्ट है.

स्रोत: पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

एनजीटी ने 18 राज्यों से अपशिष्ट जल के इस्तेमाल पर कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हाल ही में देश भर में भूजल संसाधनों पर दबाव कम करने और शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से कहा है. एनजीटी ने 18 राज्यों और 02 केन्द्र शासित प्रदेशों को अपशिष्ट जल के इस्तेमाल पर कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
- एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समक्ष तीन महीने के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

मुख्य तथ्य

- एनजीटी के अनुसार, जिन राज्यों ने अभी तक अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है वे अधिकरण के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका कोई वास्तविक कारण नजर नहीं आ रहा है.
- मात्र नौ राज्यों और पांच केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा से कार्य योजनाएं प्राप्त हुई हैं.
- जिन राज्यों ने कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की हैं, वे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी):

- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की स्थापना की गई.
- यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को संभालने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है. पर्यावरण संबंधी मामलों में अधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार तीव्र पर्यावरणीय न्याय प्रदान करेगा.
- इस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन एवं व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान हेतु सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गयी.

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत में वायु प्रदूषण से हर साल 5 साल से कम उम्र के 1 लाख बच्चों की मौतः अध्ययन

चर्चा में क्यों?

☞ पर्यावरण थिंक टैंक सीएसई के 'स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरन्मेंट (एसओई)' रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण के चलते भारत में हर साल 5 वर्ष से कम उम्र के 1 लाख बच्चों की मौत हो रही है. यह देश में होने वाली 12. 5 प्रतिशत मौतों के लिए भी जिम्मेदार है.

☞ विश्व पर्यावरण दिवस पर जारी एक अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपात स्थिति बन गई है. इस रिपोर्ट में जल, स्वास्थ्य, कचरा उत्पादन एवं निस्तारण, वनों एवं वन्यजीव को शामिल किया गया है.

मुख्य तथ्यः

- रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषित हवा के कारण भारत में करीब 10,000 बच्चों में से औसतन 8.5 बच्चे पांच साल का होने से पहले मर जाते हैं. यह खतरा बच्चियों में सबसे ज्यादा है क्योंकि 10,000 लड़कियों में से 9. 6 पांच साल का होने से पहले मर जाती हैं.
- भारत में वायु प्रदूषण होने वाली 12.5 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार है. इसका प्रभाव बच्चों पर उतना ही चिंताजनक है. खराब हवा के चलते देश में करीब 1,00,000 बच्चों की पांच साल से कम उम्र में मौत हो रही है.
- थिंक टैंक के अनुसार, वायु प्रदूषण से लड़ने की सरकार की योजनाएं अब तक सफल नहीं हुई हैं और इस तथ्य को पर्यावरण मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है. इससे पहले वायु प्रदूषण पर वैश्विक रिपोर्ट में सामने आया था कि साल 2017 में इसके चलते भारत में 12 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी.
- ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है.

पृष्ठभूमि

- भारत ने साल 2013 में संकल्प लिया था कि गैर इलेक्ट्रिक वाहनों को हटा दिया जाएगा और साल 2020 तक 1.5 से 1.6 करोड़ हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा था.
- हालांकि सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार, ई-वाहनों की संख्या मई 2019 तक करीब 2.8 लाख थी जो तय लक्ष्य से काफी पीछे है.

स्रोतः द हिंदू

आयरलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

☞ आयरलैंड की संसद ने 09 मई 2019 को जलवायु आपातकाल घोषित कर दिया है. आयरिश की संसद ने एक संसदीय रिपोर्ट में संशोधन की घोषणा की, जिसमें बिना किसी वोट के आपातकाल की घोषणा की गई थी.

☞ संसदीय रिपोर्ट ने संसद से यह भी जांच करने का आह्वान किया कि कैसे आयरिश सरकार जैव विविधता हानि के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में सुधार कर सकती है.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का दूसरा देश

- आयरलैंड जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का दूसरा देश बना गया है. इससे पहले ब्रिटेन जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है.
- ब्रिटेन की संसद ने 01 मई 2019 को जलवायु आपातकाल घोषित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया था, जिससे वह जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था.

ग्रीनहाउस प्रभाव

- ग्रीनहाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में सहयता करतीं हैं.
- इन ग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाई आक्साइड, जल-वाष्प, मिथेन आदि गैस शामिल हैं. यदि ग्रीनहाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही धरती पर जीवन होता. अगर ग्रीनहाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 सेल्सियस होता न कि वर्तमान 15 सेल्सियस होता.
- धरती के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं जिसमें से ग्रीनहाउस प्रभाव एक कारक है.

जलवायु परिवर्तन क्या है?

- पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद से साल दर साल बढ़ रहा है. जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइपीसीसी) की रिपोर्ट ने पहली बार इससे आगाह किया था.
- अब इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं. इसके दुष्परिणाम गर्मियां लंबी होती जा रही हैं, और सर्दियां छोटी. विश्वभर में ऐसा हो रहा है.
- प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति एवं प्रवृत्ति बढ़ चुकी है. ऐसा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण हो रहा है.

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइपीसीसी)

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइपीसीसी) अन्तर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है. यह संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है.
- यह पैनल जलवायु में बदलाव एवं ग्रीनहाउस गैसों का ध्यान रखता है. इस पैनल को साल 2007 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

स्रोतः द हिंदू

विश्व पर्यावरण दिवसः 05 जून

चर्चा में क्यों?

- विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 2019 को विश्व भर में मनाया जा रहा है. हरेक विश्व पर्यावरण दिवस पर पृथक आयोजक देश का चयन होता है जहां आधिकारिक समारोह का आयोजन किया जाता है. पहला विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 1974 को मनाया गया था.
- विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी. इनमें प्रकृति के प्रति चिंता और उसके सरंक्षण की भावना भी निहित है.

विश्व पर्यावरण दिवस के थीम और उद्देश्य:

- प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम- 'वायु प्रदूषण' है.
- इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरुक करना तथा पर्यावरण के लिए कार्य करना है.

विश्व पर्यावरण दिवस

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1972 में मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था. इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके दो साल बाद, 05 जून 1974 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया.
- साल 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग-अलग देशों को चुना जाता है.
- इसमें हरेक साल 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं.

मुख्य उद्देश्य:

- इस वैश्विक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक चेतना और वैश्विक सरकारों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण को केंद्र में रखते हुए विश्व के देशों में राजनीतिक चेतना जागृत करना था. भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले पर्यावरण दिवस पर भारत की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंताओं को जाहिर किया था.

स्रोत: द हिंदू

शोधकर्ताओं द्वारा हिम युग के समयावधि का समुद्री जल खोजा गया

चर्चा में क्यों?

- शोधकर्ताओं द्वारा हिन्द महासागर में की गई खोज के परिणामस्वरूप पहली बार हिम युग के समय का समुद्री जल खोजा गया है. शोधकर्ताओं का दावा है कि यह जल समुद्र के भीतर चट्टानी श्रृंखलाओं की दरारों में मौजूद था जो हजारों वर्षों से वहीँ पर मौजूद है.
- यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के शोधकर्ताओं द्वारा एक माह तक चले इस अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया. यह खोज मालदीव में समुद्री तल पर मौजूद चूना पत्थर की चट्टानों के अध्ययन के दौरान हुई है.

मुख्य बिंदु

- शोधकर्ताओं द्वारा एक विशेष शिप, JOIDES Resolution, का प्रयोग किया गया जो कि समुद्री तल तक जाने और समुद्री चट्टानों में ड्रिल करने की सुविधा से लैस है. इसके माध्यम से समुद्र में तीन मील भीतर तक खुदाई की गई.
- इसके बाद वैज्ञानिक मशीनरी द्वारा पानी को बाहर निकाल देते हैं या तलछट से पानी निचोड़ने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग करते हैं.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस खोज से पहले तक वैज्ञानिक समुद्री जल के पुनर्निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर थे जैसे – जीवाश्म कोरल तथा समुद्र तल पर अवसाद की मौजूदगी.
- वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने समुद्र के भीतर से लगभग 20,000 साल पुराना पानी खोज निकाला है.
- वैज्ञानिक वास्तव में उन चट्टानों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे यह निर्धारित किया जा सके कि क्षेत्र में मानसून चक्र से प्रभावित होकर तलछट कैसे बनती है.
- वैज्ञानिकों का कहना है कि यह समुद्री जल आमतौर पर मिलने वाले समुद्री जल से कहीं अधिक खारा था.

JOIDES रिजोल्यूशन

- JOIDES रिजोल्यूशन (JR) एक शोध पोत है जो कोर के नमूनों को इकट्ठा करने और उनका अध्ययन करने के लिए समुद्र तल में ड्रिल करता है. जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान और पृथ्वी के इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक जेआर से डेटा का उपयोग करते हैं. यह इंटरनेशनल ओशियन डिस्कवरी कार्यक्रम का एक हिस्सा है और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित है. इस शिप पर समुद्री तल से 62 मीटर ऊपर तक की उंचाई की ड्रिल मशीन लगी है. इस पर लगी ड्रिल मशीन से समुद्र के भीतर 8,235 मीटर तक की गहराई तक पहुंचा जा सकता है.

ELITE IAS

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अन्य खबरें

पाकिस्तान ने भारत में मोईन उल हक को अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया

- पाकिस्तान ने राजनयिक मोईन उल हक को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है. यह जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने देते हुए कहा कि भारत से द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से नई दिल्लीत देश के लिए काफी महत्वचपूर्ण है. यही कारण है कि हम मोईन उल हक को भारत भेज रहे हैं.

पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

- भाजपा के वरिष्ठ नेता पेमा खांडू ने 29 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की. अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी डी मिश्रा ने यहां दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में पेमा खांडू को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई.
- उनके अलावा चोवना मेन समेत मंत्रिमंडल के 11 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की. इस शपथ ग्रहण समारोह में असम, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की हैं.

देश की पहली महिला 'वित्तमंत्री' बनीं निर्मला सीतारमण

- निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बन गई हैं. निर्मला सीतारमण उन महिला नेताओं में से एक हैं जो बेहद कम समय में राजनीति के शिखर तक पहुंची हैं. देश की पहली रक्षा मंत्री रहीं निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है.
- हालांकि उनसे पहले तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पीएम पद के साथ-साथ वित्त मंत्री का कार्यभार 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक संभाला था, लेकिन अभी तक किसी भी महिला को वित्तमंत्री के रूप में स्वंत्रत रूप से पद नहीं मिला था. इस कारण से निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्तमंत्री बनी गई हैं. निर्मला सीतारमण को पिछली सरकार में रक्षा मंत्री और उससे पहले कॉरपोरेट कार्य का मंत्री बनाया गया था. वह साल 2008 में भाजपा का हिस्सा बनीं और तभी से पार्टी से जुड़ी हुई हैं.

अजीत डोभाल पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को केंद्र सरकार द्वारा पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है. इसके अतिरिक्त अजीत डोभाल को मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है. अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया गया है. उनकी नियुक्ति अगले पांच वर्ष के लिए की गई है.
- गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की वायुसेना की रणनीति को मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमलीजामा पहनाया था. उन्होंने वायुसेना, नौसेना के शीर्ष अधिकारियों से रणनीति पर चर्चा करके इसे तैयार किया था.

भारतीय लेखिका एनी जैदी को नाइन डॉट्स प्राइज 2019 का विजेता घोषित किया गया

- भारतीय लेखिका एनी जैदी को एक लाख डॉलर के नाइन डॉट्स प्राइज 2019 का विजेता घोषित किया गया. यह पुरस्कार उन्हें उनकी प्रविष्टि 'ब्रेड, सीमेंट, कैक्टस' के लिए दिया गया है. यह पुस्तक भारत में उनके

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

समसामयिक जीवन के बेहतर अनुभवों में रचे-बसे स्मरण और घर एवं संपत्ति की अवधारणा को तलाश करते रिपोर्ताज का मिश्रण है

- यह एक प्रतिष्ठित पुस्तक पुरस्कार है जो विश्व भर के समसामयिक मुद्दों को उठाने वाले नवोन्मेषी विचारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है. नाइन डॉट्स प्राइज नए लोगों को बिना सीमा या अंकुश के सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है. इसका मुख्य उद्देश्य नवीन सोच को बढ़ावा देना है.

वाइस एडमिरल करमबीर सिंह ने नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला

- वाइस एडमिरल करमबीर सिंह ने एडमिरल सुनील लांबा की जगह ली है. एडमिरल सुनील लांबा 31 मई 2019 को रिटायर हो गये हैं. वाइस एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख हैं. उन्होंने नौसेना अध्यक्ष का पद संभालने के बाद कहा की यह मेरे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है.
- नौसेना प्रमुख के तौर पर वाइस एडमिरल सिंह की तत्काल प्राथमिकता नए जंगी जहाजों, पनडुब्बियों एवं विमानों को शामिल कर भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण में लंबे समय से चली आ रही देरी को जल्द से जल्द पूरा करना है. फिलहाल भारतीय नौसेना में लगभग 132 जहाज, 220 विमान और 15 पनडुब्बियां हैं.

जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

- 30 मई 2019 को वाईएसआर कांग्रेस चीफ जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. आंध प्रदेश के राज्यपाल ई एस एल नरसिम्हा ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलवाई. उनके शपथ ग्रहण समारोह द्रमुक पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मौजूद रहे. जगनमोहन रेड्डी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अन्य पार्टियों के दिग्गज नेता भी शामिल हुए.
- मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा चुनाव में अपनी हार को स्वीकार करते हुए राज्यपाल ई.एस.एल. नरसिम्हन को अपना इस्तीफा सौंपा दिया था. राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और चंद्रबाबू नायडू को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने काम को जारी रखने के लिए कहा था.

नवीन पटनायक ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

- ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 29 मई 2019 को भुवनेश्वर में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. ओडिशा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल ने नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलायी. उन्होंने लगातार पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है.
- मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. पटनायक से पहले मात्र दो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु और सिक्किम में पवन चामलिंग पांच बार मुख्यमंत्री रहे.

ISSF वर्ल्ड कप: शूटर सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता

- 27 मई 2019 को भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने जर्मनी के म्यूनिख में चल रहे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) विश्व कप में पुरूषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में नये विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता. सौरभ चौधरी पहले ही टोक्यो ओलंपिक के लिये कोटा हासिल कर चुके हैं.
- सौरभ चौधरी पहले दौर के शॉटस के बाद चेरसुनोव से 0.6 अंक पीछे थे. दूसरे दौर के छह शॉट में हालांकि उन्होंने बढ़त हासिल कर ली. उन्होंने इसमें तीन शाट में 10 से कम अंक बनाये लेकिन दो शाट 10.7 के लगाये. चौधरी का अंतिम शॉट 10.6 का था जिससे वह खुद का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहे.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने की इस्तीफे की घोषणा

- 24 मई 2019 को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कंजर्वेटिव पार्टी की नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. उन्होंने ब्रेक्जिट को लेकर अपने प्रदर्शन पर अफसोस जताते हुए यह घोषणा किया है. वे 07 जून 2019 तक इस पद पर रहेंगी. जब तक नए प्रधानमंत्री का नाम तय नहीं हो जाता तब तक वह पीएम पद पर बनी रहेंगी.
- थेरेसा मे के इस्तीफे की घोषणा से ब्रेक्जिट का मामला और उलझ गया है. अब नए प्रधानमंत्री पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वह शर्तो पर सबको साथ लेकर संसद में विधेयक पारित कराए या फिर बिना शर्त यूरोपीय यूनियन से अलग होने की घोषणा करे.

गोपाल श्रेष्ठ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एचआईवी संक्रमित पर्वतारोही बने

- नेपाल की राष्ट्रीय फुटबाल टीम के खिलाड़ी रह चुके श्रेष्ठ ने यह उपलब्धि अपने दूसरे प्रयास में हासिल की. गोपाल श्रेष्ठ को 25 साल पहले संक्रमित इंजेक्शन लगने की वजह से एचआईवी हो गया था. नेपाल की समाचार एजेंसी राष्ट्रीय समाचार समिति के अनुसार, गोपाल श्रेष्ठ ने 22 मई 2019 को सुबह 8.15 बजे 8848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर कदम रखा.
- गोपाल श्रेष्ठ का माउंट एवरेस्ट फतेह करने का यह दूसरा प्रयास था. उन्होंने साल 2015 में पहला प्रयास किया था, लेकिन भूकंप आने के कारण एवरेस्ट बेस कैंप से उन्हें वापस लौटना पड़ा था. गोपाल श्रेष्ठ का यह दूसरा प्रयास उनके श्स्टेप-अप अभियान: एवरेस्ट मुहिम का दूसरा चरणश का हिस्सा था. इसके तहत वह समाज और देश में एचआईवी से प्रभावित बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए जागरूकता फैलाते हैं.

ओमान की लेखिका जोखा अल्हार्थी को बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला

- जोखा अल्हार्थी को उनकी किताब 'सेलेस्टियल बॉडीज' के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है. अल्हार्थी ने यह पुरस्कार जीतकर ओमान में इतिहास रच दिया है. जोखा अरबी भाषा की पहली लेखिका हैं, जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है. बुकर पुरस्कार के जजों की समिति इस पुस्तक की इन्हीं खूबियों को विश्व के सामने लाना चाहती है.
- जोखा अल्हार्थी को बुकर पुरस्कार में जीत के रूप में पचास हजार पाउंड अर्थात 44 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिलेगी. उन्होंने इस रकम को अपने उपन्यास 'सेलेस्टियल बॉडीज' की अनुवादक अमेरिका की मर्लिन बूथ के साथ बांटने का फैसला किया है. यह पुरस्कार 'सेलेस्टियल बॉडीज' ने यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पांच प्रविष्ठियों को पछाड़कर हासिल किया है.

World Cup 2019: अफगानिस्तान में पहली बार होगा वर्ल्ड कप का प्रसारण

- इस योजना के तहत आईसीसी प्रशंसकों तक क्रिकेट की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल माध्यमों के अतिरिक्त समाचार, सिनेमा, फैन पार्क और विभिन्न अन्य मीडिया साझेदारों की घोषणा की. आईसीसी ने पुरूष क्रिकेट विश्व कप 2019 का प्रसारण वैश्विक प्रसारण साझेदार स्टार स्पोर्ट्स के अलावा 25 साझेदारों के साथ 200 से ज्यादा देशों में करना सुनिश्चित किया है.
- इस बार विश्व कप में खिलाड़ी अपनी जर्सी के अंदर ट्रैकर डिवाइस (वेस्ट) पहनेंगे. इसकी सहायता से मैदान पर खिलाड़ियों के मूवमेंट को मॉनीटर करने में मदद मिलेगी. इसकी मदद से फिजियो और ट्रेनर यह जान सकेंगे कि किस खिलाड़ी को आराम की जरूरत है और कौन घायल हुआ है

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

जोको विडोडो लगातार दूसरी बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने

- निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक परिणाम की समय से पूर्व अचानक 21 मई 2019 को घोषणा की. विडोडो पांच साल के लिए दोबारा इस पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं. आयोग ने बताया कि इंडोनेशियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल के सदस्य जोको विडोडो ने अपने प्रतिद्वंदी एवं सेवानिवृत्त जनरल प्राबोवो सुबियांतो को हराया.
- जोको विडोडो का जन्म 21 जून 1961 को हुआ था. सुबियांतो और सुहार्तो के सैन्य शासन के दौरान जोको विडोडो इंडोनेशिया की सेना के जनरल रह चुके हैं. जोको विडोडो साल 2014 में इंडोनेशिया के सातवें राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए थे. इस चुनाव में इंडोनेशिया में धार्मिक मुद्दे काफी हावी रहे हैं. हालांकि समझा जाता है कि जोको विडोडो की चुनावी जीत के बाद उनके दूसरे कार्यकाल में इंडोनेशिया में लोकतंत्र और भी मजबूत बन सकता है.

इरफान पठान सीपीएल खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय

- कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2019 के खिलाड़ियों के ड्रॉफ्ट घोषणा की गई जिसमें इरफान में एकमात्र भारतीय हैं.
- इरफान पठान अगर सीपीएल की नीलामी में खरीद लिए जाते हैं तो वह किसी बड़ी विदेशी टी-20 लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे. नीलामी के लिए तैयार 20 देशों के कुल 536 खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में इरफान पठान को शामिल किया गया है.
- इरफान पठान पिछले दो सीजन में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में हिस्सा नहीं ले सके थे. वे पिछली बार साल 2017 में गुजरात लायंस के लिए खेले थे. तब उन्हें केवल एक मैच में खेलने का मौका मिला था. वे साल 2016 में पुणे सुपरजाएंट्स के लिए केवल चार मैच खेले थे.

जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाले पहली महिला बनी

- जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गयी हैं. वह तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपनी सेवाएं दे सकती हैं. क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई महिला मैच रेफरी बनी है. आईसीसी की तरफ से एक बयान में बताया गया कि जीएस लक्ष्मी तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय मैचों में रेफरी की भूमिका निभाने के योग्य हो गई हैं.
- ऑस्ट्रेलिया की इलोइस शेरिडन आईसीसी के अंपायरों के 'डेवलपमेंट पैनल' में ऑस्ट्रेलिया के पोलोसाक के साथ जुड़ेंगी. इस तरह से इस पैनल में महिलाओं की संख्या सात हो गई है. इस पैनल में लॉरेन एगेनबाग, किम कॉटन, शिवानी मिश्रा, सू रेडफर्न, मैरी वाल्ड्रान और जैकलिन विलियम्स शामिल अन्य महिला अधिकारी हैं. इस पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला अंपायर कैथी क्रॉस थीं, जिन्होंने साल 2018 में संन्यास ले लिया था.

IPL 2019 Final: मुंबई इंडियन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर चौथी बार खिताब जीता

- मुंबई इंडियन्स ने चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है. हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 149 रन बनाये लेकिन चेन्नई की टीम 20 ओवरों में सात विकेट पर 148 रन ही बना पाई.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच रहे जबकि केकेआर के आंद्रे रसल सबसे कीमती खिलाड़ी रहे, उन्होंने 510 रन बनाये जबकि 11 विकेट लिए. चेन्नई की टीम के खिलाड़ी शेन वॉटसन (80) की शानदार पारी के बावजूद 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर टीम सिर्फ 148 रन ही बना सकी. वॉटसन ने 59 गेंदों की अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के मारे.

विश्व तंबाकू निषेध दिवस:31 मई

- 31 मई 2019 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व भर में मनाया गया. इस दिवस पर तंबाकू उत्पादों का अवैध व्यापार स्वास्थ्य, कानूनी और आर्थिक, शासन और भ्रष्टाचार सहित प्रमुख वैश्विक चिंता का विषय है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सभी देशों से तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने की अपील की है ताकि नये लोगों को तंबाकू सेवन का आदी होने से बचाया जा सके.
- पूरे विश्व के लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने हेतु तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिये तंबाकू चबाने या धुम्रपान के द्वारा होने वाले सभी परेशानियों से बचाने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य देशों ने साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाये जाने की घोषणा की थी.

लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के कमांडर नियुक्त

- भारतीय सेना के इन्फैंट्री स्कूल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर को हाल ही में दक्षिण सूडान (यूएनएमआईएसएस) में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कमांडर नियुक्त किया गया. यह दूसरा सबसे बड़ा शांति अभियान है.

  संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 24 मई 2019 को घोषणा करते हुए कहा कि शैलेश तिनेकर रवांडा के लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक कामांजी के कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे. लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक कामांजी का कार्यकाल 26 मई 2019 को पूरा हो रहा है.

प्रसिद्ध बिरहा गायक पद्मश्री हीरालाल यादव का निधन

- भारत के प्रसिद्ध बिरहा गायक हीरालाल यादव का 12 मई 2019 को वाराणसी में निधन हो गया. वे 93 वर्ष के थे. हीरालाल का जन्म वर्ष 1936 में चेतगंज स्थित सरायगोवर्धन में हुआ था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च 2019 को हीरालाल को पद्मश्री से सम्मानित किया था.

विश्व अस्थमा दिवस 07 मई को मनाया गया

- विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है. इस बार विश्व अस्थमा दिवस 07 मई 2019 को विश्व स्तर पर मनाया गया. वर्तमान समय में वायु प्रदूषण को देखते हुए अस्थमा के रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है.
- विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में घोषित किया गया है. विश्व अस्थमा दिवस साल 1998 में पहली बार बार्सिलोना, स्पेन सहित 35 देशों में मनाया गया. विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा (जीआईएनए) द्वारा किया जाता है.

72वां कांस फिल्म महोत्सव, 2019

- 14-25 मई, 2019 के कांस फिल्म महोत्सव का 72वां संस्करण फ्रांस के शहर कांस में आयोजित किया गया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस महोत्सव में बांग जून-हो (Bong Joon&ho) द्वारा निर्देशित दक्षिण कोरियाई फिल्म गिसाएंगछुग (GISAENG CHUNG) (पैरासाइट) को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार (PALM D'OR) प्रदान किया गया।
- महोत्सव का शुभारंभ अमेरिकी फिल्म निर्देशक की कॉमेडी फिल्म 'द डेड डोंट डाय' (The Dead Don't Die) से किया गया।

महोत्सव में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं-

- ग्रैंड प्रिक्स-एटलानटीक (ATLANTIQUE) एटलानटिक्स (Atlantics) निर्देशक-मती डायोप (Mati Diop)।
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक-विगगो मोर्टेसन (Viggo Mortensen), (फिल्म-LE JEUNE AHMED)।
- ज्यूरी प्राइज-लेस मिजरेबल्स (LES Miserables), (निर्देशक- Ladj LY)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता-एंटोनियो बैंडेरास (Antonio Banderas), (फिल्म-Dolar Gloria)।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री-एमिली बीछम (Emily Beecham) (फिल्म-लिटिल जोए (स्पजजसम श्रवम)।
- सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म (Palm D' OR)- द डिस्टैंस बिटवीन अस एंड द स्काई (The Distance Between Us and the Sky) (निर्देशक-वासीलिस केकाटोस (Vasilis KEKATOS)

ELITE IAS

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009